राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 10 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-283 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पीएम मोदी बोले: फालतू पेपरवर्क खत्म हो

नियम-कानून परेशानी के लिए नहीं, जिंदगी आसान बनाने के लिए हो, बार-बार डेटा जमा करना बंद करना होगा

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंगलवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पीएम ने बैठक में कहा- मैं फालतू पेपरवर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार-बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, 'कोई भी कानून आम लोगों के लिए परेशानी नहीं बनना चाहिए। नियम-कानून लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। सुधार सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं, समाज के हर क्षेत्र में होने चाहिए।' बैठक में पीएम ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार जीत के शिल्पकार हैं। सरकार ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन की इजाजत देकर नागरिकों पर भरोसा किया। इस बात पर जोर दिया कि यह भरोसा बिना किसी गलत इस्तेमाल के 10 साल से कामयाबी से काम कर रहा है। ईज ऑफ लाइफ और ईफ ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। देश अब पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है, जहां सुधार तेजी से और साफ इरादे से हो रहे हैं।सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं, न कि सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू-केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकें। पीएम मोदी 11 दिसंबर को NDA के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

राज्यों में एसआईआर के काम में 'बाधा' पर अदालत सख्त

कहा: ईसी संज्ञान में लाए, हम आदेश पारित करेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को धमकाने के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में कथित तौर पर बाधा डालने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की कमी को गंभीरता से लेने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने कहा, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पुलिस तो तैनात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास सभी सांविधानिक शक्तियां हैं, जिससे हम बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं से डील कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निपटें वरना इन हालातों से अराजकता हो सकती है। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कामकाज की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) नियुक्त किया है।

यूपी: परिवहन निगम के ड्राइवर-कंडक्टरों का बढ़ा वेतन

अब प्रति किलोमीटर मिलेगा इतना पैसा

एजेंसी

लखनऊ। रोडवेज में संविदा चालकों/परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इन्हें 14 से सात पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। पुनरीक्षित दर से मानदेय का भुगतान परिवहन निगम द्वारा एक जनवरी 2026 से किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि नोएडा क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र, सौनोली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज डिपो के संविदा चालकों/परिचालकों को औसतन 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है। अन्य क्षेत्रों के संविदा चालक/परिचालक के मानदेय सात पैसे प्रति किमी की बढ़ोत्तरी की गई है। योजना में चालकों को दो वर्ष की निरंतर सेवा एवं परिचालकों को चार वर्ष की निरंतर सेवा जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की ड्यूटी एवं 66000 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी। ऐसे में चालक के लिए पारिश्रमिक 14687, प्रोत्साहन 4000 यानी कुल करीब 18687 रुपये मिलेंगे। परिचालक को पारिश्रमिक 14418, प्रोत्साहन 4000 मिलेगा।

शाह बोले: वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस के खून में है

लोकसभा में गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, खड़गे ने वंदे मातरम् के नारे लगाए

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत ह्यवंदे मातरम्ह्न पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जो लोग वंदे मातरम् के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा था कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? मैं बताती हूं- क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। हालांकि शाह ने जवाब में प्रियंका का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर कल सदन (लोकसभा) में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य (राहुल-प्रियंका) नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में

है। दरअसल राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से सालभर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। अमित शाह ने कहा, जिस गान को गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा गीत कहा, वो वंदे मातरम् का टुकड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। वंदे मातरम् ने आजादी के आंदोलन को गति दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखाजी कामा और वीर सावरकर ने भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर भी स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम लिखा था- वंदे मातरम् । भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम् गान के समय सम्मान के साथ कड़ा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के जिस जिस सांसद ने वंदे मातरम् नहीं गाने पर बयान दिया। सदन से बाहर चले गए, मैं इसकी लिस्ट आज शाम तक सदन के पटल पर रख दूंगा। इस सदन के चर्चा के रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि कांग्रेस के सांसद वंदे मातरम् का विरोध करते हैं बंकिम चंद्र की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने एक स्टांप जारी किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान भी हमने शुरू किया। और आह्वान किया था तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम् का कहना भूलना नहीं है। अमित शाह ने कहा, गुलामी के कालखंड में वंदे मातरम् गीत ने घनघोर अंधेरे के बीच लोगों के मन में आजादी के खिलाफ लड़ने का जोश जगाया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर कल सदन (लोकसभा) में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य (राहुल-प्रियंका) नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है।

ममता बनर्जी आक्रामक: कहा: पीएम मोदी माफी मांगें

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहकर अपमान किया

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहकर उनका अपमान किया है। कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का तब जन्म भी नहीं हुआ था, जब देश को आजादी मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को इतने साधारण तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपने (पीएम मोदी) उन्हें वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जिसके वह हकदार हैं। आपको इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लेखक का जिक्र किया।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने 'दा' शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री से 'बंकिम बाबू' कहने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने तुरंत उनकी भावना स्वीकार करते हुए कहा, मैं बंकिम 'बाबू' कहूंगा। धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। इसके बाद हल्के अंदाज में पीएम ने पूछा कि क्या वह अब रॉय को भी 'दादा' कह सकते हैं।

सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड (TCR) मंगाया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस दौरान सोनिया और राज्य

सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। यह याचिका विकास त्रिपाठी ने दायर की है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सोनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वे भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनीं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सका, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में दो बार तब शामिल हुआ, जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। मालवीय ने पर लिखा, 'यह पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं, जो अयोग्य या अवैध हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का विरोध करते हैं।'

गोवा क्लब अग्निकांड: थाईलैंड भागे दोनों मालिक

एजेंसी

गोवा। अरपोरा गांव में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में 6 दिसंबर की देर रात लगी आग के कुछ घंटे बाद ही क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। पुलिस ने हादसे के बाद FIR दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की थी। 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला कि वे इंडिगो फ्लाइट 6ई 1073 से देश छोड़ चुके थे। पुलिस के मुताबिक दोनों 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ही इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट रवाना हो गए। गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव

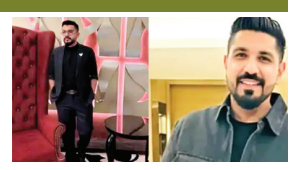

लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी कर दिया है। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने वागाटोर में सौरभ और गौरव लूथरा की रोमियो लेन बीच शैक को गिराने का आदेश दिया है। इधर, जमीन के असली मालिक प्रदीप घाडी अमोनकर ने न्यूज एजेंसी से कहा कि क्लब नमक के खेतों पर अवैध रूप से बनाया गया था। यह मामला 20 साल से कोर्ट में चल रहा है। पणजी से 25 दूर बने क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

ट्रम्प बोले: भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा

सस्ता चावल भेज रहा, जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाली खाद पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रम्प ने यह बात सोमवार को व्हाइट हाउस में उस समय कही, जब वे किसानों के लिए नई आर्थिक मदद की घोषणा कर रहे थे। ट्रम्प ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में बहुत सस्ता चावल बेच रहे हैं, जिससे यहां के किसानों की कमाई कम हो रही है। उन्होंने इसे 'डंपिंग' बताया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रम्प ने अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है। मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कनाडा से आने वाली खाद पर भी कड़े टैरिफ लगा सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी खाद कनाडा से आती है। अगर यह बहुत सस्ती हो गई तो हम उस पर सख्त टैरिफ लगा देंगे। कनाडा ,अमेरिका को पोटाश खाद की सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। अब तक इसे

व्यापार समझौते की वजह से संरक्षण मिला हुआ है। अमेरिका में महंगाई और बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रम्प पर दबाव बढ़ रहा है। किसान भी बढ़ती लागत से परेशान हैं। अगर खाद पर नया टैरिफ लग गया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने हाल ही में पोटाश और फॉस्फेट को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किया था, ताकि उनकी सप्लाई बनी रहे, लेकिन किसान अभी भी इसे लेकर परेशान हैं। ट्रम्प ने मेक्सिको को यह आरोप लगाते हुए 5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी कि वह अमेरिका को तय समझौते के मुताबिक पानी नहीं दे रहा। यह समझौता लगभग 80 साल पुराना है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से मेक्सिको पर इसके पालन न करने का आरोप लगाता है। ट्रम्प ने किसानों की मदद के लिए 12 अरब डॉलर का एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि फसलों के दाम कम हो गए हैं और चीन सहित कई देशों के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के कारण अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पैकेज के तहत ज्यादातर पैसा किसानों को सीधी मदद के रूप में दिया जाएगा ताकि वे अपनी फसलें बेच सकें और अगले साल की खेती की तैयारी कर सकें। सोयाबीन और ज्वार उगाने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इन फसलों का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। लेकिन इस साल चीन ने अमेरिकी सामान पर नई ड्यूटी लगाने के बदले में अमेरिकी सोयाबीन खरीदना लगभग बंद कर दिया, जिससे किसानों की इनकम काफी घट गई। डंपिंग का मतलब है कि कोई देश अपनी चीजें दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है। यह इतना कम होता है कि वहां की लोकल कंपनियां और किसान उस कीमत पर सामान बना ही नहीं पाते। इससे उस देश का बाजार सस्ते विदेशी माल से भर जाता है और स्थानीय लोगों का कारोबार नुकसान में चला जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे लोकल मार्केट पर विदेशी कंपनियों या प्रोडक्ट का कब्जा हो जाता है।

उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे परियोजना के खिलाफ आरएसएस

एनवायरमेंटलिस्ट बोले- 7 हजार देवदार के पेड़ कटेंगे, मां गंगा सूख जाएगी, बर्फबारी नहीं होगी

एजेंसी

उत्तरकाशी। उत्तराखंड में केन्द्र और राज्य सरकार की महत्त्वकांक्षी गंगोत्री हाईवे परियोजना यानी ऑल वेदर रोड के खिलाफ संघ यानी फर खुलकर विरोध में आ गया है। फर के सह-सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने परियोजना के तहत 7 हजार देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध किया है। इसके बाद रविवार को उत्तरकाशी के हर्षिल में 100 से ज्यादा लोगों ने देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। इसको समर्थन देने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पहुंचे। इसी दौरान वरिष्ठ पत्रकार राहुल कोटियाल ने भी देवदार के पेड़ में रक्षा सूत्र बांधा। एनवायरमेंट एक्सपर्ट आयुष जोशी ने बताया कि ये पेड़ भागीरथी इकोनॉमिक सेंसेटिव जोन में काटे जाएंगे, जिससे गंगा का पानी सूख जाएगा। इसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा और बर्फबारी में कमी दर्ज की जाएगी। इसी साल नवंबर में उत्तराखंड के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज के एक लेटर के अनुसार, ऑल वेदर रोड के कारण 41.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान होगा, जिसमें कई देवदार

के पेड़ भी शामिल हैं। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि 900 किलोमीटर लंबी परियोजना में कुल 56 हजार से ज्यादा पेड़ काटे जाने थे, जिनमें से लगभग 36,000 पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में 889 किलोमीटर लंबा एक महत्वाकांक्षी राजमार्ग नेटवर्क बनाना चाहती है, जिसका उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे चार प्रमुख तीर्थ स्थलों को साल भर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ताकि मानसून या बर्फबारी के दौरान भी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इस परियोजना में पुरानी सड़कों को चौड़ा करना (लगभग 10-12 मीटर तक), उन्हें पक्का करना और भूस्खलन जैसी समस्याओं से बचाने के लिए मॉडर्न तकनीकी का उपयोग करना शामिल है। जिसे दिसंबर 2016 से शुरू किया गया था। जिसके के लिए 12,769 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चार धाम परियोजना की हाई पावर कमेटी के सदस्य डॉ. हेमंत ध्यानी ने बताया कि इस परियोजना के तहत गंगोत्री घाटी और हर्षिल घाटी के हजारों देवदार के पेड़ों को कटा जाना है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के हो सकारात्मक प्रयास

(लेखक - रमेश सर्राफ धमोरा)

(10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस पर विशेष)

हम 10 दिसंबर को मानवाधिकारों का उत्सव मनाते है। उस दिन की स्मृति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा हमारे समाजों के मानवाधिकार ढांचे की रीढ़ है, जहां हममें से प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के शांति और सुरक्षा के साथ रहने और फलने-फूलने का अधिकार है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया था। 75 वर्ष पहले पारित हुआ विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर हैं। जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। 10 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिज्ञाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 77वीं वर्षगांठ है । 2025 में मानवाधिकार दिवस की थीम हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, तीन सरल सत्यों पर जोर देती हैं। मानवाधिकार सकारात्मक हैं, मानवाधिकार आवश्यक हैं, और मानवाधिकार प्राप्य हैं।

मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है। कुछ अधिकार ऐसे होते है जो व्यक्ति को जन्मजात मिलते है। उन अधिकारों का व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता।

देश के विशाल आकार व विविधता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है। भारतीय परिदृश्य में यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हैकि क्या वाकई में मनुष्य के लिए चिन्हित किये गए मानवाधिकारों की सार्थकता है।

भारत में 28 सितम्बर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,19,20,21,23,24,39,43,45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित हैं।

कहने में मानवाधिकार शब्द बहुत बड़ा है। क्योंकि मानवाधिकारो से हर व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। आज के दौर में कोई भी मानव को उनके वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहता है। राजनेता मानव अधिकार की बात तो जोरशोर से करते हैं। मगर जब अधिकार देने की बारी आती है तो पीछे खिसकने लगते हैं। राज नेताओं को पता है कि यदि लोगों को उनके अधिकार मिल गये तो तो उनकी नेतागिरी बन्द हो जायेगी। हमारे देश के संविधान में मानव को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। मगर उन पर अमल नहीं हो पाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिये बनाये गये कानून महज कागजो में सिमट कर रह जाते हैं।

इतिहास गवाह है की भारत ने कभी भी संस्कृति, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर दूसरों को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की है। भारत एक ऐसा देश है जिसके मूल में मानवाधिकार की अवधारणा है। भारत के लोग मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर आज भी मानवाधिकार का समर्थन करता रहा है। मानवाधिकार दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझ कर और उसको महसूस कर रखी गई थी। किसी भी इंसान की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकार का नाम ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इन अधिकारों की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोडने वाले को अदालत सजा भी देती है।

पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों-सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शख्स को बराबरी का अधिकार देना लोकतंत्र का अहम घटक है। यही वजह है कि आज ज्यादातर सरकार इस अधिकार को कायम करने की कोशिश कर रही है। इंसानी अधिकार हमारे अस्तित्व और दुनिया में आत्मसम्मान से रहने की गारंटी होते हैं। हमारी भौतिक और आत्मिक सुरक्षा बरकरार रखते हुए लगातार तरक्की में अहम होते हैं। इसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, प्रवास का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीडन पर रोक, महिला हिंसा, असमानता, धार्मिक हिंसा पर रोक जैसे कई मजबूत कानून बनाए गए हैं। यही वजह है कि हर लोकतांत्रिक देश मानवाधिकार अधिकारों की सशक्त पैरवी करते नजर आते हैं।

इस दुनिया में जो भी मानव जन्म लेता है उसके साथ उसके कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है तो कुछ समाज, कुछ अधिकार हमारा मुल्क देता है, तो कुछ दुनिया। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो अपने अधिकारों से अंजान है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग भेदभाव के जरिए तो कभी रंग भेद नीति को अपनाकर लोगों के इन अधिकारों को कुचला जा रहा है। हर तबके, हर शहर और दुनिया के कोने-कोने में किसी न किसी वजह से लोगों को बराबरी के हक से महरूम रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में हुई बड़ी से बड़ी क्रांति के पीछे अधिकारों का हनन ही अहम वजह रही है। हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए इंसान को लंबी जंग लडनी पड़ी है। दुनिया में तमाम जगह लोगों ने अपन हक की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां दी हैं और आज भी बहुत से लोग अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गए और उनको लागू करने या करवाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन वह सिर्फ कागजी दस्तावेज बन कर रह गए हैं। समाज में मानवाधिकारों के होने वाले उल्लंघन के प्रति अगर मानव ही जागरूक नहीं है तो फिर इनका औचित्य क्या है? देखे तो पता चलेगा की कितने मानवाधिकारों का हनन मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। मानव के द्वारा मानव के दर्द को पहचानने और महसूस करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे मन में मानवता है ही नहीं तो फिर हम साल में पचासों दिन ये मानवाधिकार का झंडा उठा कर घूमते रहें कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

सरकार भी मानवाधिकारो का हनन रोक पाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही है। देश में आये दिन मानवाधिकार हनन की घटनायें घटित होती रहती है। मगर सरकारी स्तर पर शख्त कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है। जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति पर रोक लग सके। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का लगातार हनन होता रहता है।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

वंदे मातरम का उद्घोष

यह सुखद ही है कि कृतज्ञ राष्ट्र देश के स्वतंत्रता सेनानियों में ओज का संचरण करने वाले गीत वंदे मातरम के सृजन के डेढ़ सौ साल पूरे होने को एक उत्सव की तरह मना रहा है। स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत करोड़ों भारतीयों में इस गीत ने आजादी का जज्बा भरा था। लाखों स्वतंत्रता सेनानी इस गीत से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो जाते थे। इस पावन वेला में देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सही मायनों में यह अवसर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है। इस गीत की सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की दृष्टि से देखा था। इसी आलोक में वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर लोकसभा में इस पर चर्चा का शुरू होना सुखद ही है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब इस गीत के सृजन के पचास साल पूरे हुए तो देश परतंत्र था। जब इसके सौ साल पूरे हुए तो देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, फलत- उस दौर में इस गीत को जनता व स्वतंत्रता सेनानियों का सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। निस्संदेह,बंकिम चंद्र चटर्जी की इस रचना ने बंगाल में क्रांतिकारियों को गहरे तक प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि, विपक्ष इसे सुर्खियों में लाने के फैसले के राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा है। वे इसके समय को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि में जन्मे इस ओज के गीत को बंगाली समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़कर देखा। खासकर बंगाल विभाजन के बाद इसे बंगाल की अस्मिता पर फिरंगियों के प्रहार के दौर में एक मरहम के तौर पर देखा। निस्संदेह, देश ऐसे स्मरण उत्सव का हकदार है, मगर वे चुनावी नजरियों से मुक्त हों। विपक्ष की दलील है कि जब पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो इस गीत के प्रसंगवश राजनीतिक लाभ-हानि के तर्क गढ़े जा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन में वंदे मातरम को एकता के सूत्रधार के रूप में सराहा गया। लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा हुई। दरअसल, उन्होंने जब भी कांग्रेस की आजादी से पहले और बाद की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया या फिर ऐतिहासिक विवादों का नये सिरे से जिक्र किया, तो विपक्ष ने उसे निशाने पर लिया। विपक्षी दलील है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की कवायद में वैचारिक विभाजन को हवा दी जा रही है। कहा गया कि पश्चिम बंगाल, जहां इस गीत का जन्म हुआ, वहां की सांस्कृतिक पहचान राजनीति से जुड़ी रही है। वंदे मातरम एक भावनात्मक प्रतीक है और इसीलिए एक रणनीतिक प्रतीक भी। दरअसल, विपक्ष की नाराजगी राजग सरकार की उस प्रवृत्ति को लेकर है जिसमें वह सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक अखाड़े में बदल रही है। उन्हें आशंका है कि साझी विरासत पर चिंतन के लिये आयोजित विमर्श का उपयोग चुनावी लाभ अर्जित करने के लिये किए जाने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी जड़ें जमाए हुए है, फिर भी उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा का ममता बनर्जी द्वारा समर्थन किया जाना दर्शाता है कि वह इस मुद्दे को छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। विडंबना ही है कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में ओज भरने वाले गीत के विमर्श में चिंतन की गंभीरता प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल आज बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहा है।

मानवाधिकारः वैश्विक मानचित्र पर स्याह धब्बे और उम्मीद की किरणें

(लेखक - दिलीप कुमार पाठक)

10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस)

शांति केवल वहीं कायम रह सकती है जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, जहां लोगों को भोजन मिलता है, और जहां व्यक्ति और राष्ट्र स्वतंत्र हैं - दलाई लामा

दुनिया में मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक है, जहाँ आधुनिक दासता, संघर्षों में उल्लंघन, अभिव्यक्ति पर रोक और भेदभाव जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ताइवान में यौन उत्पीड़न कानून और बुयुकाडा मानवाधिकार रक्षकों की रिहाई जैसी कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मानवाधिकारों के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और संघर्ष जारी है द्य दुनिया के कई हिस्सों में सरकारों द्वारा असहमति की आवाजों को दबाने और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के मामले बढ़े हैं। नस्ल, रंग, लिंग, जातीयता, धर्म, या अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव अभी भी व्यापक रूप से मौजूद है, जिससे कमजोर आबादी प्रभावित हो रही है।

मानव अधिकारों को लेकर आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवाधिकार व मानव की बुनियादी मुक्ति पर घोषणा की थी। साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसम्बर की को विश्व मानवाधिकार दिवस तय किया। 65 वर्ष से पहले हुआ पारित विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर है, जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। मानवाधिकार का मतलब किसी भी इंसान की ज़िंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है द्य भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ़ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को कानून सजा भी देता है द्य

मानव अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है जैसे - हर इंसान को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार है। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया। इस आयोग का काम नागरिक-राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की देख-रेख करना है। इसमें बाल-मज़दूरी, एचआईवी/एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल-विवाह, महिला अधिकार, हिरासत में मौत, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार आदि शामिल हैं। इन सभी अधिकारों को बचाना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य लक्ष्य है।

हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, काम, घर, संस्कृति, खाना और मनोरंजन जैसी बुनियादी चीज़ों का अधिकार है—इन्हें ही विश्व मानवाधिकार घोषणा में बताया गया है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में बहुत गरीबी है, और यही गरीबी बहुत सारे लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखती है। इन जगहों पर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की ज़रूरतें अक्सर पूरी नहीं हो पातीं। साथ ही, नस्लवाद और जाति-भेद भी मानवाधिकारों की रक्षा में बड़ी रुकावट बनते हैं। सरल शब्दों में- गरीबी और भेदभाव लोगों को उनका हक नहीं मिलने देते।

मानव के जन्म लेने के साथ ही उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए कुछ अधिकार उसको स्वतः मिल जाते हैं और वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिकार एक मनुष्य होने के नाते प्राप्त हो जाता है। चाहे वह अपने हक के लिए बोलना भी जानता हो या नहीं। एक नवजात शिशु को दूध पाने का अधिकार होता है और तब वह बोलना भी नहीं जानता। लेकिन माँ उसको स्वयं देती है और अगर नहीं देती है तो उसके घरवाले, डॉक्टर सभी उसको इसके लिए कहते हैं, क्योंकि ये उस बच्चे का हक है और ये उसे मिलना ही चाहिए। एक बच्चे के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए ये ज़रूरत सबसे अहम होती है। लेकिन उसके बड़े होने के साथ-साथ उसके अधिकार भी बढ़ने लगते हैं। बच्चे के पढ़ने-लिखने और अपनी परवरिश आदि के लिए उसको समुचित सुविधाएँ और वातावरण देना भी ज़रूरी अधिकारों में आता है। उन्हें आत्म-सम्मान के साथ जीने के लिए, अपने विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ हालात ऐसे चाहिए, जिससे की उनके रास्ते में कोई व्यवधान न आये। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,19,20,21,23,24, 39,43,45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दिशा में आयोग के अतिरिक्त कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ समाजसेवी लोग भी इस दिशा में अकेले ही अपनी मुहिम चला रहे हैं। मानवाधिकार दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा करना और इसे बढ़ावा देना सभी का कर्तव्य है, ताकि हम एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण कर सकें।

(लेखक पत्रकार हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

चैतन्य रहें

एक बार दो देवताओं में विवाद हो गया कि भाग्य बड़ा है या पुरूषार्थ? विवाद हर व्यक्ति के मन में पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। निश्चित हुआ, परीक्षा करें। एक देवता ने कहा- देखो! भाग्य बड़ा नहीं होता, पुरूषार्थ बड़ा होता है। दूसरे ने कहा- नहीं! उस आदमी को देखो। तुम्हें साक्षात् प्रमाणित करूंगा कि पुरूषार्थ बड़ा नहीं होता, भाग्य बड़ा होता है।

पति-पत्नी जा रहे थे। देवता ने रास्ते के बीच रत्नों का ढेर लगा दिया। रत्न ही रत्न बिखेर दिए। जब आस-पास आए, पत्नी ने कहा- अभी तो हमारी आंखे अच्छी हैं, हम देख सकते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़ापा आने के साथ-साथ हमारी आंखें चली जाएं, हम अन्धे हो जाएं। फिर काम कैसे चलेगा? पति ने कहा - परीक्षा कर लें। देखें, कैसे काम चलेगा? दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। दोनों चले। जहां रत्न बिखरे हुए पड़े थे, ढेर लगा था आस-पास में, उससे आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर पति बोला- आंखो के बिना काम तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खोल लो पट्टी। पट्टी खोल ली। देवता ने कहा - देखा तुमने! भाग्य में नहीं था, कुछ नहीं मिला। भाग्य बड़ा है पुरूषार्थ से। भाग्य और पुरूषार्थ की चर्चा को हम छोड़ दें किन्तु इस बात को हम नहीं छोड़ेंगे कि जब तक आंख पर मूर्च्छा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक हमारे आस-पास में, हमारे सामने, दाएं-बाएं, चारों तरफ जो सम्पदा बिखरी पड़ी है, उसका हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम उस सम्पदा से अनजान रह जाते हैं।

विचार मंथन

75 साल बाद संसद में वंदे मातरम की राजनीति?

(लेखक-सनत जैन)

नई पीढ़ी जानेगी वंदे मातरम का इतिहास, मां किसी से भेदभाव नहीं करती

स्वतंत्र भारत की संसद में 75 वर्षों के बाद 'वंदे मातरम' पर हुई चर्चा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक प्रयास के रूप में शुरू हुई। वंदे मातरम की यह चर्चा एक गीत या नारे तक सीमित नहीं रही। यह बहस प.बंगाल के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण, उसकी सांस्कृतिक चेतना और एकता के भाव को समझने का अवसर भी बन गई। संसद में सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों ने एकजुट होकर वंदे मातरम के पक्ष में बढ़-चढ़कर अपने विचार व्यक्त किये।वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। बल्कि वह स्वर है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्योति जगाई थी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत आज भी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके बोल हर किसी को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर देते हैं।संसद में इस विषय पर हुई चर्चा का सबसे बड़ा महत्व यह है, नई पीढ़ी को वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और तकनीक की दुनिया में व्यस्त है। ऐसे विषय पर संसद में जो सार्थक बहस हुई है। वर्तमान पीढ़ी को सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से स्वतंत्रता के इतिहास और वर्तमान में प.बंगाल के चुनाव में इस नारे का क्या महत्व है। यह जानने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी यह जान सकेगी राष्ट्र की पहचान केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि उसके गौरवपूर्ण अतीत से भी बनती है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को इस नारे ने विफल कर दिया था। धर्म, भाषा, प्रांत, गरीब और अमीर सब इस नारे से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। संसद में बहस के दौरान यह बात भी उभरकर सामने आई।'मां' किसी से भेदभाव नहीं करती है। वंदे मातरम में जिस मां की वंदना की गई है। वह भारत माता है।जो अपने सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखती है। चाहे वह किसी भी भाषा, धर्म, जाति या किसी भी क्षेत्र से हो। यह गीत किसी एक वर्ग, समुदाय या धर्म का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। वंदे मातरम को संकीर्ण नजरिये से देखना ना केवल इसके भाव को सीमित करता है। बल्कि राष्ट्रीय एकता अखंडता और भारतीय संस्कृति को भी चोट पहुंचाता है। हाल के वर्षों में वंदे मातरम को लेकर समय-समय पर राजनीतिक लाभ के लिए विवाद खड़े होते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इसे विवाद का विषय बना रहे हैं। संसद में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वंदे मातरम के इस नारे ने स्वतंत्रता की जो लो आम जनमानस के बीच में जगाई थी। सबने बढ़ चढ़कर इस नारे के औचित्य को समझाया।संसद में हुई बहस ने यह स्पष्ट किया, देशभक्ति किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, अभिव्यक्ति के माध्यम अलग-अलग भी हो सकते हैं। यह दिल से उपजने वाली भावना है। वंदे मातरम का सम्मान करना और उसके भाव को समझना सभी नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता है। हां अभिव्यक्ति के तरीके जरूर अलग-अलग हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले इसे विवाद का विषय बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरूरत इस बात की है, हम वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीति से ऊपर उठकर देखें। यह गीत सारे भारत को एक साथ जोड़ता है। इसका एक-एक शब्द सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में हुई बहस नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने में संसद की यह चर्चा सार्थक साबित होगी। वंदे मातरम के नारे का जन्म पश्चिम बंगाल से हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में इसके नारे देश के सभी प्रांतों मे गूंजे। दुनिया में सैकड़ो रामायण विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। सब में अलग-अलग तरीके से राम का वर्णन किया गया है। ठीक उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वंदे मातरम गीत को प्रत्येक भाषा में अलग-अलग तरह से इसे विभिन्न बोल और विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग संगीत की धुन में गाया गया है। वंदे मातरम में प्रत्येक गीत और संगीत में एक सा भाव है। वंदे मातरम के इस नारे से हमने स्वतंत्रता पाई है। अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति को सफल नहीं होने दिया। जैसे ही इस नारे ने भारत को एकजुट किया। अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। संसद में वंदे मातरम विषय पर जो बहस हुई है। प्रत्येक सांसद ने वंदे मातरम के पक्ष में बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। वंदे मातरम को लेकर जो राजनीति पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तारतम्य में प्रयास किया जा रहा है। उसमें कितनी सफलता मिलेगी, यह तो भविष्य ही तय करेगा। संसद में जिस तरह से सांसदों ने वंदे मातरम को लेकर ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। संसद में हुई बहस ने नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन और वंदे मातरम के महत्व को समझाने में जरुर मदद की है। प. बंगाल में धार्मिक धुव्रीकरण का जो प्रयास वंदे मातरम के माध्यम से करने के प्रयास को कितनी सफलता मिलेगी? यह कहना मुश्किल है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत की संप्रभुता संसाधनों और ऊर्जा प्रणालियों पर निर्भर- अदाणी

- अदाणी ने खनन को नई अर्थव्यवस्था की नींव बताया

धनबाद । अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस) के 100वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत की संप्रभुता उसके प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा प्रणालियों पर नियंत्रण पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक देश केवल अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं, ऐसे में भारत को अपना विकास मार्ग स्वयं निर्धारित करना होगा। अदाणी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए बताया कि बख्तियार खिलजी और ब्रिटिश शासन ने भारत की स्वतंत्रता और शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत सपने नहीं बेचता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है। उन्होंने कथात्मक उपनिवेशीकरण की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व में सबसे कम है। अदाणी ने आईआईटी (आईएसएम) के छात्रों के लिए इंटर्नशिप और अदाणी 3एस माइनिंग एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की घोषणा की। अदाणी ने खनन को नई अर्थव्यवस्था की नींव बताया और जोर दिया कि भारत को संसाधनों, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में संप्रभु क्षमताएं विकसित करनी चाहिए।

हिमाचल में कृषि सेवाओं के लिए दरें तय, छोटे किसानों को राहत

ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों से सेवाओं के लिए मनमाने दाम वसूलने पर लगेगी रोक

हमीरपुर । हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने हमीरपुर जिले में छोटे किसानों की शिकायतों के बाद फसलों की बुवाई, कटाई और 'थ्रेसिंग' के लिए दरें तय की हैं। इससे पहले कई क्षेत्रों में ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों से सेवाओं के लिए मनमाने दाम वसूले जा रहे थे। कृषि विभाग के एक अे धिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर से जुताई और बुवाई की दर 1,200 रुपये प्रति घंटा, रोटावेटर से जुताई की दर 1,320 रुपये प्रति घंटा और कटाई तथा थ्रेसिंग की दर भी 1,320 रुपये प्रति घंटा तय की गई है। इसके अलावा, पावर टिलर से बुवाई 500 रुपये प्रति घंटा, रीपर से कटाई 1,300 रुपये प्रति घंटा और ब्रश कटर से कटाई 400 रुपये प्रति घंटा होगी। अे धिकारी ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक वसूलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थ्रेसिंग में भूसे और तिनकों से अनाज अलग किया जाता है। इस फैसले से छोटे किसानों को उचित मूल्य पर कृषि सेवाएं मिलेंगी और उन्हें मनमाने दाम वसूलने की परेशानी से राहत मिलेगी।

जेएसडब्ल्यू स्टील का नवंबर में कच्चा इस्पात उत्पादन 5 फीसदी बढ़ा

- उत्पादन वृद्धि से मजबूत हुई कंपनी की स्थिति

नई दिल्ली ।

उद्योगपति सज्जन जिंदल की अगुवाई में जेएसडब्ल्यू स्टील ने नवंबर में अपने एकीकृत कच्चा इस्पात उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने बीएसई को बताया कि नवंबर में उत्पादन 24.39 लाख टन रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 23.23 लाख टन था। इस वृद्धि को कंपनी के निरंतर विस्तार और प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग में मजबूती का संकेत बताया गया है। नवंबर में जेएसडब्ल्यू स्टील के भारतीय परिचालन का उत्पादन भी 5 प्रतिशत बढ़कर 23.61 लाख टन पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि भारतीय परिचालन में क्षमता उपयोग 84 प्रतिशत रहा। यह कम उपयोग विजयनगर संयंत्र में 'ब्लास्ट फर्नेस' को बंद करने के कारण हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील, 23 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले जेएसडब्ल्यू समूह का प्रमुख कारोबार है। समूह की उपस्थिति ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सीमेंट, पेंट, रियल एस्टेट, ई-प्लेटफॉर्म, परिवहन, रक्षा, खेल और उद्यम पूंजी जैसे क्षेत्रों में है। इस उत्पादन वृद्धि से जेएसडब्ल्यू स्टील की देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थिति और प्रगाढ़ हुई है।

ओला इलेक्ट्रिक ने तैनात की 250 सदस्यीय स्पेशल टीम

नई दिल्ली । दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने बढ़ते सर्विस बैकलॉग, रिपेयर में देरी और स्पेयर पार्ट्स उपलब्धता की समस्या को देखते हुए 250 सदस्यों की एक स्पेशल रैपिड-रिस्पॉन्स टीम पूरे देश में तैनात की है। कंपनी ने ग्राहकों की सर्विस से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस टीम का मिशन पेंडिंग रिपेयर को तेज करना, सर्विस नेटवर्क को मजबूत बनाना और ग्राहकों को भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सपोर्ट देना है।

ओला ने बताया कि हायपरसर्विस मॉडल के तहत सर्विस सिस्टम को पूरी तरह नए ढंग से तैयार किया जा रहा है। इस मॉडल का मकसद उन सामान्य समस्याओं को खत्म करना है, जिनका सामना ग्राहकों को अक्सर करना पड़ता है जैसे लंबी वेटिंग, रिपेयर में देरी और पार्ट्स की कमी। कंपनी का दावा है कि बेंगलुरु में इसे पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और अब इसे कई बड़े शहरों में विस्तार दिया जा रहा है। नई 250-सदस्यीय टीम में अनुभवी टेक्नीशियन, ऑपरेशनल और मैनेजमेंट विशेषज्ञ शामिल हैं, जो विशेष रूप से बैक-लॉग रिपेयर, बैटरी रिप्लेसमेंट और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई को तेज करने पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मेट्रो शहरों में सर्विस देरी में स्पष्ट कमी देखने को मिली है। इसके अलावा, ओला ने इन-ऐप सर्विस बुकिंग फीचर भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए ग्राहक सीधे ऐप से सर्विस स्लॉट बुक कर सकते हैं और जरूरी पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इससे सर्विस सेंटर जाने की जरूरत कम होगी और समय की बचत होगी। 2023 में रिकॉर्ड बिक्री के बाद स्कूटरों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिसके चलते सर्विस नेटवर्क पर भारी दबाव पड़ा।

भारत में एआई प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य कॉपीराइट लाइसेंस का प्रस्ताव

- कॉपीराइट धारकों के लिए वैधानिक रॉयल्टी और पारिश्रमिक का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा

नई दिल्ली । उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एआई और कॉपीराइट से जुड़े नए नियामक दृष्टिकोण के लिए एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति में कानूनी विशेषज्ञ, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एआई प्रशिक्षण में कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री के उपयोग और मौजूदा कानून की समीक्षा करना था। समिति ने एआई डेवलपर्स को सभी वैध रूप से उपलब्ध कॉपीराइट सामग्री तक पहुंच देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस की सिफारिश की है। इसके साथ ही कॉपीराइट धारकों के लिए वैधानिक रॉयल्टी और पारिश्रमिक का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत व्यक्तिगत बातचीत की आवश्यकता समाप्त होगी और लेनदेन लागत घटेगी। मॉडल का उद्देश्य एआई नवाचार को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण के लिए डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करना, और स्टार्टअप एवं एमएसएमई के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। कॉपीराइट धारकों को न्यायिक रूप से तय रॉयल्टी, आसान भुगतान प्रक्रिया और उचित मुआवजा मिलेगा। समिति ने यह भी स्वीकार किया कि एआई प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता है, और इसके लिए संतुलित नियामक ढांचा बनाना आवश्यक है। इससे न केवल मानव निर्मित कार्यों की सुरक्षा होगी, बल्कि एआई नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। डीपीआईआईटी ने 30 दिनों में हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है।

पीएम मोदी के पुतिन को केसर भेंट करने से जम्मू-कश्मीर के किसानों की उम्मीदें बढ़ीं

अनंतनाग।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक दर्शाने वाले विशेष तोहफे भेंट किए। इन उपहारों में कश्मीर का मशहूर केसर और भगवद्गीता का रूसी संस्करण शामिल रहा। यह उपहार न केवल भारत की कला, आध्यात्मिकता और परंपरा को दर्शाते हैं बल्कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करते हैं।

कश्मीर के बुरहान दीन ने इस कदम पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कश्मीरी केसर उपहार में दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जम्मू-कश्मीर के लोगों से विशेष लगाव है। वह चाहें तो कोई कीमती वस्तु भेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कश्मीर की पहचान केसर को चुना। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे केसर की पैदावार बढ़ाएं, क्योंकि अब यह दुनिया के शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता सईद अख्तर हुसैन ने कहा कि कश्मीर की हर वस्तु अनमोल है और उसी अनमोलता का प्रतीक यहां का केसर है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीरी केसर को विश्व पटल पर और प्रख्यात कर दिया है। यदि किसान इसकी खेती को बढ़ावा दें तो यह वैश्विक स्तर पर और बड़ी पहचान बना सकता है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम होगी। जम्मू-कश्मीर में केसर की सबसे अधिक पैदावार होती है और प्रधानमंत्री द्वारा इसका चयन करना हमारे लिए गर्व की बात है।

कश्मीर घूमने आए पर्यटकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया। एक पर्यटक ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा पुतिन को कश्मीरी केसर भेंट करने से हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई है। हम यहां का असली केसर खरीदकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यहां के किसान मेहनती हैं और केसर की खेती को बढ़ावा देना चाहिए।

इंडिगो की 4,500 उड़ानें रद्द होने से विमानन राजस्व प्रभावित

नुकसान की भरपाई के लिए विमानन कंपनी से मुआवजे पर किया जा रहा है विचार

नई दिल्ली।

पिछले सप्ताह इंडिगो ने लगभग 4,500 उड़ानें रद्द कीं, जिससे देश के प्रमुख निजी हवाई अड्डा संचालकों का विमानन राजस्व प्रभावित हुआ। वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस नुकसान की भरपाई के लिए विमानन कंपनी से मुआवजे पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा, हमारी आपसी समझ और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संकट के स्थिर होने तक अंतिम निर्णय टाला गया है। हवाई अड्डों का बड़ा हिस्सा राजस्व विमानन गतिविधियों से आता है, जिसमें लैंडिंग और पार्किंग शुल्क शामिल हैं। ये शुल्क विमानन कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाते हैं, लेकिन अक्सर टिकट की कीमतों में शामिल कर यात्रियों पर आंशिक या पूर्ण रूप से डाल दिया जाता है। हालांकि, गैर-विमानन राजस्व जैसे खुदरा बिक्री, ड्यूटी-फ्री, लाउंज सेवाएं और अन्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उनका योगदान अभी भी कुल राजस्व में विमानन के मुकाबले कम है। हवाई अड्डे सीधे यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क भी लेते हैं, जो सुरक्षा, सुविधा और अन्य सेवाओं में उपयोग होता है। कुछ हवाई अड्डों पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क भी लिया जाता है,

जिसका उपयोग हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डे इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सभी उड़ानें सामान्य होने के बाद ही नुकसान के आकलन और मुआवजे के निर्णय पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी 1.2 अरब डॉलर की नई ऋण सहायता

- पिछले साल पा किस्तान को 7 अरब डॉलर की मदद मिली थी

इस्लामाबाद । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत करीब 1.2 अरब डॉलर की नई ऋण सहायता मंजूर की है। इसमें विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत 1 अरब डॉलर और जलवायु-केंद्रित टिकाऊ स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) के तहत 20 करोड़ डॉलर शामिल हैं। पाकिस्तान वर्तमान में आईएमएफ के 24वें कार्यक्रम में है, जिसके तहत पिछले साल उसे 7 अरब डॉलर की मदद मिली थी। आईएमएफ के एक अे धिकारी ने कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और निजी क्षेत्र-नेतृत्व वाली मध्यम अवधि की वृद्धि हासिल करने के लिए विवेकपूर्ण नीतियों और सुधारों को तेज करना होगा। इस्लामाबाद के अधिकारियों ने इसे आर्थिक सुधारों और व्यापक प्रबंधन में विश्वास का प्रतीक बताया। आईएमएफ ने पिछले महीने वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

बीज प्रमाणीकरण न कराया तो होगी वसूली: कृषि मंत्री

- बीज विकास निगम से विक्रय में देरी पर जताई नाराजगी

लखनऊ ।

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने 27 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को चेतावनी दी है, जिन्होंने अभी तक बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकरण नहीं कराया। मंत्री ने कहा कि यदि एफपीओ तुरंत पंजीकरण नहीं कराएंगे तो सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की वसूली की जाएगी। उन्होंने 32 एफपीओ के उत्पादित बीज के उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा अब तक न खरीदने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि निदेशालय में प्रदेश के 100 एफपीओ के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें 24 एफपीओ ने अब तक 80,960 क्विंटल बीज का उत्पादन और निगम को विक्रय किया। मंत्री ने कहा कि एफपीओ केवल गेहूं और धान ही नहीं, बल्कि दैंचा के बीज भी प्रमाणित कर निगम को बेचेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, निदेशक कृषि, निदेशक बीज विकास निगम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

स्टारलिंक ने भारत में सेवा की कीमतों पर दी सफाई, सही दरें अभी घोषित नहीं

- वेबसाइट पर दिखाई गई मासिक 8,600 और उपकरण लागत 34,000 रुपए वास्तविक नहीं थीं

मुंबई । अमेरिकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवा की कीमतों को लेकर स्पष्ट किया है कि वेबसाइट पर दिखाई गई मासिक 8,600 रुपए और उपकरण लागत 34,000 रुपए वास्तविक नहीं थीं। कंपनी ने बताया कि यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी। स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट अभी लाइव नहीं है और ऑर्डर भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बिजनेस ऑपरेशंस अे धिकारी ने कहा कि टीमें अंतिम सरकारी मंजूरी और सुरक्षा परीक्षणों के बाद ही सेवा चालू करेंगी। बांग्लादेश में स्टारलिंक की मासिक योजनाएं 40-50 (3,400-4,300 रुपए) और उपकरण 300-400 डॉलर (25,800-34,400 रुपए) हैं। वहीं श्रीलंका में मासिक 100-125 डॉलर (8,600-10,750 रुपए) और उपकरण 900-1,000 डॉलर (77,400-86,000 रुपए) हैं। डाउनलोड स्पीड 190-360 एमबीपीएस के बीच है। ईलॉन मस्क का कहना है कि स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरों के बजाय ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लिए अधिक लाभकारी होगी। शहरों में सेल टावर पर्याप्त हैं, लेकिन गांवों में ब्रॉडबैंड बिछाना महंगा और मुश्किल है। भारतीय दूरसंचार कंपनियों को डर है कि स्टारलिंक के आने से 5जी और फिक्स्ड

वायरलेस एक्सेस योजनाओं पर असर पड़ सकता है। स्टारलिंक जियो-एसईएस और भारती समर्थित यूटेलसेट वनवेब जैसी सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। कंपनी को उपयोगकर्ताओं के टर्मिनल और उपग्रहों के बीच सिग्नल भेजने के लिए कई गेटवे अर्थ स्टेशन स्थापित करने होंगे। एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी से इन कंपनियों के रिटेल नेटवर्क के माध्यम से स्टारलिंक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

चावल कंपनियों के शेयर लड़खड़ाए, 10 फीसदी तक फिसले

ट्रंप के बयान से निवेशक चिंतित, सबसे अधिक गिरावट एलटी फूड्स के शेयर में दर्ज की गई

मुंबई । भारतीय चावल कंपनियों के शेयर मंगलवार को बाजार खुलते ही तेज गिरावट के साथ खुले। केआरबीएल, एलटी फूड्स और जीआरएम ओवरसीज़ जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयर 3 से 10 फीसदी तक फिसल गए। सबसे अधिक गिरावट एलटी फूड्स के शेयर में दर्ज की गई, जो 8 फीसदी गिरकर 362 रुपए के इंट्रा-डे लो पर आ गया। कोहिनूर फूड्स के शेयर 10 फीसदी तक घट गए, जबकि चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शेयर 5 फीसदी नीचे गया। इसके अलावा कावेरी सीड कंपनी और जीआरएम ओवरसीज़ लिमिटेड के शेयर भी प्रभावित हुए। हालांकि दिन के दौरान कुछ शेयरों में रिकवरी भी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत से आयातित चावल और कनाडा से आने वाले फर्टिलाइज़र पर नए टैरिफ लगा सकता है। उनका कहना था कि ये आयात अमेरिकी किसानों के लिए चुनौती बन रहे हैं और अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम से सस्ते चावल आने से अमेरिकी किसानों की उपज की कीमतें दब रही हैं और इसे लेकर कदम उठाना आवश्यक है। उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर का सहायता पैकेज भी घोषित किया। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय चावल निर्यातकों के शेयरों में पैनिक सेलिंग हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका चावल पर टैरिफ लागू करता है, तो इसका दीर्घकालीन असर निर्यातकों की आय और शेयर बाजार पर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए सतर्क रहना और बाजार की चाल पर ध्यान देना जरूरी है।

भारत बनेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब : इंटेल-टाटा की साझेदारी से सेमीकंडक्टर क्रांति तेज

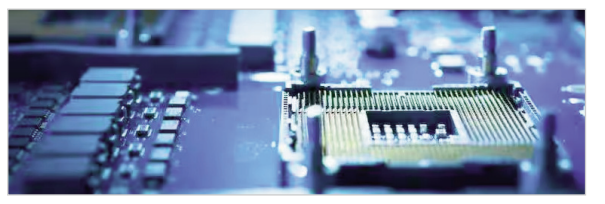

1.18 लाख करोड़ निवेश से गुजरात और असम में तैयार होंगी अत्याधुनिक चिप फैक्ट्रियां

नई दिल्ली । भारत अब केवल मोबाइल और कंप्यूटर उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी चिप दिग्गज इंटेल और देश के प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा समूह ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस समझौते के तहत भारत में चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और असेम्बली की जाएगी, जिससे देश के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को नई मजबूती मिलेगी। टाटा समूह के अनुसार, इंटेल के उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के धोलेरा में बन रही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में होगी, जबकि उनकी पैकेजिंग और टेस्टिंग असम में स्थापित किए जा रहे टाटा के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर एसेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट (ओएसएटी) में की जाएगी। इन दोनों अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए टाटा समूह लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यह निवेश भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है।

साझेदारी का एक बड़ा फोकस एआई सक्षम कंप्यूटर सिस्टम तैयार करना भी होगा, जिसकी वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया के टॉप-5 पीसी मार्केट्स में शामिल होगा। ऐसे में इस पहल से घरेलू बाजार में न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन को गति मिलेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इंटेल एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने इसे भारत के बढ़ते कंप्यूटिंग बाजार के लिए रणनीतिक फैसला बताते हुए कहा कि एआई और पीसी की बढ़ती मांग भारत को एक महत्वपूर्ण टेक डेस्टिनेशन बना रही है।

इस्पात-सीमेंट उद्योग में कार्बन उत्सर्जन घटाने की पहल

भारत और स्वीडन ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली ।

भारत के इस्पात और सीमेंट क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए टाटा स्टील, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स और जिंदल स्टील जैसी अग्रणी कंपनियों ने स्वीडिश प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर सात नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। ये पहल भारत के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों का हिस्सा है। इन परियोजनाओं में रोटरी भट्टों में हाइड्रोजन का उपयोग करके इस्पात निर्माण, 'स्टील स्लैग' के पुनर्चक्रण से हरित सीमेंट का उत्पादन, और कृत्रिम मेधा (एआई) के माध्यम से सीमेंट के कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे उपाय शामिल हैं। इन सभी पहल का उद्देश्य कठिन-उद्योग क्षेत्रों को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना है। सात प्री-पायलट परियोजनाओं को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वीडिश ऊर्जा एजेंसी से वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा। प्रमुख भागीदारों में प्रौद्योगिकी कंपनियां कंथल और स्वेरिम, तथा भारतीय शैक्षणिक संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी

भुवनेश्वर, आईआईटी हैदराबाद और दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शामिल हैं। ये परियोजनाएं न केवल भारत के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को समर्थन देंगी, बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईपीएल 2026 की नीलामी सूची घोषित; 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने 2026 सीज़न के लिए खिलाड़ियों की नीलामी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। आईपीएल द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस सूची में 350 खिलाड़ी शामिल हैं, जिन पर 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली आगामी नीलामी में बोली लगाई जाएगी। नीलामी के लिए पंजीकृत 1,390 खिलाड़ियों में से 350 को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सूची में 224 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो इस साल की नीलामी में नई प्रतिभा और गहराई ला रहे हैं।

फ्रेंचाइज़ी कुल 77 उपलब्ध स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिनमें से 31 विशेष रूप से विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। 350 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ियों ने खुद को अधिकतम आधार मूल्य 2 करोड़ रुपये में सूचीबद्ध किया है, जिनमें वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई केवल दो भारतीय हैं। नीलामी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे (यूएई समयानुसार दोपहर 1:00 बजे) शुरू होगी। 40 खिलाड़ियों ने अपनी आरक्षित कीमत 2 करोड़ रुपये रखी है, जबकि 9 खिलाड़ी 1.5 करोड़ रुपये की श्रेणी में हैं। चार खिलाड़ियों ने 1.25 करोड़ रुपये और 17 खिलाड़ियों ने 1 करोड़ रुपये की आरक्षित कीमत चुनी है। 75 लाख रुपये की श्रेणी में 42 खिलाड़ी हैं और चार खिलाड़ियों ने 50 लाख रुपये की श्रेणी चुनी है।

इसके अलावा, सात खिलाड़ियों का आरक्षित मूल्य 40 लाख रुपये है, और 227 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा समूह 30 लाख रुपये के वर्ग में है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिनके सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक होने की उम्मीद है, क्योंकि कई टीमें एक आक्रामक ऑलराउंडर की तलाश में होंगी, ने बल्लेबाज के रूप में पंजीकरण कराया है और पहले सेट में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, जॉर्ज लिंडे और श्रीलंका के दुनिथ वेल्लालेज, जो पहले सूची में नहीं थे, को अंतिम रोस्टर में शामिल किया गया है।

दुर्गेश्वरी राठौर का अन्तर्विश्वविघालयीन हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयन

धार (एजेंसी)। खेल और युवा कल्याण विभाग धार द्वारा संचालित हॉकी फीडर सेंटर धार की प्रशिक्षणार्थी दुर्गेश्वरी राठौर का चयन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर के अन्तर्विश्वविद्यालय हॉकी दल में चयन हुआ है। दुर्गेश्वरी राठौर ने होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर में आयोजित संभाग स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेकर श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन कर इस उपलब्धि को प्राप्त किया।

उक्त प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तरीय अन्तर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता दिनांक 09 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक बालाघाट में सम्पन्न होगी। इसके पश्चात् यह दल पूणे (महाराष्ट्र) में आयोजित जोनल स्तरीय अन्तर्विश्वविद्यालयीन में भाग लेगी।

दुर्गेश्वरी राठौर की इस उपलब्धि पर जिला खेल अधिकारी, राजेश शाक्य, जिला हॉकी संघ अध्यक्ष, छोटु शास्त्री, रक्षित निरीक्षक, पुरुषोत्तम बिश्नोई, खेल अधिकारी उमंग अग्रवाल ने बधाई दी।

दुर्गेश्वरी राठौर हॉकी फीडर सेंटर धार के प्रशिक्षक मनीष सोलंकी से नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। उक्त जानकारी हॉकी प्रशिक्षक मनीष सोलंकी ने दी।

विराट स्पोर्ट्सवियर ब्रांड वन8 बेचकर एजिलिटास में हिस्सेदारी खरीदेंगे

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वह अपना स्पोर्ट्सवियर ब्रांड वन8 एजिलिटास स्पोर्ट्स को बेच रहे हैं। विराट इससे मिलने वाली 40 करोड़ रुपये की रकम जिलिटास स्पोर्ट्स में ही निवेश करेंगे। अभिषेक गांगुली की एजिलिटास स्पोर्ट्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग-टू-रिटेल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। विराट इसमें एक निवेशक के तौर पर शामिल हो रहे हैं। एजिलिटास उत्पादन, आर एंड डी, ब्रांड-निर्माण और खुदरा वितरण के क्षेत्र में काम करती है। 2023 में इस कंपनी ने स्पोर्ट्स फुटवियर बनाने वाली कंपनी मोचिको शूज को खरीदा था। इससे कंपनी की घरेलू और निर्यात क्षमता बढ़ी थी।

वहीं वन8 एक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है। विराट इसके सह-संस्थापक रहे हैं। यह ब्रांड स्पोर्ट्सवियर, कपड़े, फुटवियर और एक्सेसरीज से जुड़ा हुआ है। एजिलिटास की ओर से कहा गया है कि कोहली और गांगुली के बीच पिछली कुछ समय में साझेदारी बढ़ी है। इसी के तहत ही वन8 को लेकर करार हुआ है। कंपनी ने आगे कहा कि कोहली के पास अब तक केवल वन8 में निवेश करने का विकल्प था पर एजिलिटास की उत्पादन, डिजाइन, आर एंड डी, और वितरण क्षमता को देखते हुए, उन्होंने इसका शेयरधारक बनना तय किया है।

विराट का वन8 को एजिलिटास को बेचने का फैसला भविष्य की योजनाओं के तहत ही है। वहीं विराट ने कहा, अभिषेक के साथ मेरा रिश्ता बहुत वास्तविक है। एक दिन, जब मैं यूं ही अपनी कुछ बनाने की इच्छा के बारे में बात कर रहा था, तो उसने कहा, चलो करते हैं और इस तरह वन8 शुरू हुआ। खेल ने मेरी जिंदगी बनाई है। मूवमेंट, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस ही मेरे लिए सब कुछ हैं। यही सोच ब्रांड में बदल गयी। मैं हमेशा स्टाइल के लिए स्पोर्ट्स-फर्स्ट के क्षेत्र में जाना चाहता था।वहीं अभिषेक गांगुली ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत से स्पोर्ट्स में एक हाई-परफॉर्मेंस ब्रांड बनाना है।

श्रेयस की वापसी का फैसला इसी माह जांच रिपोर्ट के बाद होगा

मुम्बई (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया दौरे में पसलियों में चोट लगने के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी का फैसला इसी माह आने वाली उनकी अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट के आधार पर होगा। उनकी वापसी अब अगले साल ही होगी। जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वे कब से आधिकारिक पुनर्वास प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इसी स्कैन के आधार पर उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी तय हो सकती है। गौरतलब है कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय के दौरान अय्यर की बाईं पसली पर चोट लगी थी, जिसके कारण वह आईसीयू में भी भर्ती थे। इसके बाद से ही उन्हें तुरंत चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चलेगा कि उनकी चोट कितनी ठीक हुई है। इसके बाद विशेषज्ञों की टीम उनका पूरा रिहैब प्लान तैयार करेगी। हल्के कंडीशनिंग से लेकर क्रिकेट-विशेष ट्रेनिंग तक का फैसला होगा। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उनकी वापसी में किसी भी तरह की जल्दबाज़ी से बचना चाहती है औरा 100 फीसदी फिट होने पर ही उन्हें खेलने दिया जाएगा। अय्यर पिछले कुछ वर्षों से एकदिवसीय टीम के मध्यक्रम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और एकदिवसीय विश्वकप में उनकी अहम भूमिका रही है। उनकी गैरमौजूदगी के कारण अब भारतीय टीम को नए विकल्पों को आजमाना पड़ा है पर कोई भी सफल नहीं रहा है। वहीं गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्केल ने बताया कि अय्यर ने शुरुआती रिहैब शुरू कर दिया है और वे लगातार प्रगति कर रहे हैं। हालांकि, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में उनका खेलना लगभग संभव नहीं है।

हेजलवुड एशेज क्रिकेट सीरीज से बाहर हुए, अब अगले साल वापसी करेंगे : मैकडोनाल्ड

ब्रिसबेन (ईएमएस)।ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण एशेज क्रिकेट सीरीज से बाहर हो गए हैं।हेजलवुड जैसे शीर्ष स्तर के गेंदबाज का टीम से बाहर होना मेलबान टीम के लिए करारा झटका कहै। अब हेजलवुड नये साल में ही खेल में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि हेजलवुड अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप से वापसी करेंगे। मैकडोनाल्ड ने कहा, 'वह सीरीज से बाहर रहेंगे और अब उनका लक्ष्य विश्वकप में खेलना होगा। एशेज से उनका बाहर होना काफी निराशाजनक है। हमें उम्मीद थी कि वह सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे पर बदकिस्मती से वह चोटिल हो गये।' गौरतलब है कि हेजलवुड पिछले एक दशक से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालते रहे हैं।वहीं राहत की बात ये है कि कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस फिट हो गये हैं और वह 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करेंगे।कमिंस ने अभ्यास भी किया है और इस दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं आई।अब तीसरे टेस्ट में कमिंस एक बार फिर कप्तानी संभालेंगे।कमिंस के नहीं रहने पर पहले दोनो ही मैचों में स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई एकादश की कप्तानी संभाली थी।

वेंकटेश अय्यर को लेकर ये क्या बोल गए केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर?

मुम्बई (एजेंसी)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद, वेंकटेश अय्यर 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की मिनी-नीलामी में वापस आ गए हैं। डीडी स्पोर्ट्स पर द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो में बोलते हुए, केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने बताया कि कैसे ट्रायल के दौरान वेंकटेश अय्यर के आँकड़ों की बजाय उनके रवैये ने उनका ध्यान खींचा।

द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो की एक विज्ञप्ति के अनुसार, नायर ने कहा कि मैंने उन्हें उनके रवैये के कारण चुना था।

पहले दिन, वेंकटेश अय्यर ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने कभी हमारी तरफ देखा या किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि उनमें बहुत ज़्यादा रवैया है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे दिन, हमने उसे खेलने का मौका दिया। आखिरी ओवर में, जब हमारे गेंदबाज़ को ऐंठन हुई, तो वेंकी बाउंड्री से चिल्लाया, %मैं आखिरी ओवर डालूँगा। उसने गेंदबाजी की और 18 रन दिए, लेकिन मुझे उसकी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की तत्परता बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि उसके लिए यह परीक्षा कम मायने रखती थी, खुद को यह साबित करने से ज़्यादा कि वह सही काम कर रहा है। यह विश्वास मेरे साथ रहा।

2021 में, वेंकटेश ने तूफानी शुरुआत की और अपने पहले सीज़न में दस मैचों में 370 रन बनाए, जिससे केकेआर फाइनल में पहुँच गया, लेकिन वे चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से हार गए। 2024 में अपने खिताब जीतने वाले वर्ष में, इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने फिर से 370 रन बनाए। 2025 में हालात मुश्किल लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने 11 मैचों में एक अर्धशतक के साथ 20.28 की औसत से 142 रन बनाए।

पांड्या जैसे ऑलराउंडर का टीम में होना जरुरी : संजय बांगड़

नई दिल्ली ।भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने कहा है भारतीय टीम के पास अभी हार्दिक पांड्या से बेहतर ऑलराउडर कोई नहीं है।पांड्या की हालांकि फिटनेस एक समस्या है और इसी कारण वह कई अवसरों पर टीम से बाहर रहे हैं।बांगड़ ने कहा, 'उस तरह का ऑलराउंडर बनने के लिए आपको अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में से किसी भी एक के बल पर टीम में जगह बनाने में सक्षम होना चाहिए।' बांगड़ ने कहा, 'टीम प्रबंधन को उनके जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के कार्यभार का प्रबंधन करना चाहिए। हार्दिक जैसा खिलाड़ी अगर पूरी तरह से फिट हो तो वह संतुलन पैदा करता है और उसकी मौजूदगी से टीम मनचाहा संयोजन तैयार कर सकती है। इसलिए उनका टीम में होना बेहद जरुरी है।' बांगड़ ने कहा, 'विश्व क्रिकेट के सभी ऑलराउंडरों को देखें तो अभी इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स जैसा कोई अन्य खिलाड़ी तैयार है।वहीं हार्दिक पांड्या के साथ भी यही स्थिति है।' पांड्या अकेले अपनी बल्लेबाजी के बल पर शीर्ष पांच में जगह बना सकते हैं।वहीं गेंदबाजी में भी वह किसी भी टीम के शीर्ष तीन तेज गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं।'वहीं हार्दिक के कार्यभार प्रबंधन पर बात करते हुए बांगड़ ने कहा कि उन्हें तीन मैच ही खेलने चाहिए।उन्होंने कहा, 'हमें देखना होगा कि वह हालातों से कैसे तालमेल बिठाते हैं।विश्व कप से पहले उन्हें कितने मैच खेलने चाहिये।ये अभी तय नहीं किया जा सकता है।' वहीं शुभमन गिल को लेकर बांगड़ ने कहा कि टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की प्रगति से उन्हें अन्य प्रारूपों में भी फायदा होगा।उन्होंने कहा, 'पिछले एक साल में टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद शुभमन का आत्मविश्वास बढ़ा है, उससे भी उन्हें लाभ हुआ है।वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट कप्तान के रूप में अतिरिक्त ज़िम्मेदारी लेने से वह एक बेहतर खिलाड़ी बन गए हैं।'

तीसरे टेस्ट में जीत के साथ सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया

-कमिंस की वापसी से गेंदबाजी मजबूत होगी : मैकडोनाल्ड

एडिलेड (एजेंसी)। एशेज में पहले दो टेस्ट मैचों में जीत से उत्साहित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अब 17 दिसंबर से शुरु होने वाले तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी। पहले दोनो ही मैच में इंग्लैंड टीम किसी भी क्षेत्र में उसके सामने टिक नहीं पायी। ऐसे सें तीसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत की प्रबल दावेदार है। इस मैच में नियमित कप्तान पैट कमिंस की वापसी से भी टीम को लाभ होगा। कमिंस एक बेहतरीन तेज गेंदबाज और उनके आने से इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कमिंट फिट नहीं होने के कारण पहले दोनो ही मैचों से बाहर थे। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, कप्तान कमिंस वापसी के लिए तैयार हैं पर एक अन्य तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड फिट नहीं होने से सीरीज से बाहर हो गये हैं।

मैकडोनाल्ड ने कहा, कमिंस की एडिलेड में तैयारी को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने पिछले चार माह से क्रिकेट नहीं खेली है पर इसके बाद भी वह लय में हैं। उन्होंने फिट होने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अभ्यास सत्र में अपनी फॉर्म और फिटनेस दिखाई है। इसलिए हमें लगता है कि वह तैयार हैं।वहीं उन्होंने कहा कि पिछले टेस्ट से बाहर उस्मान ख्वाजा को एडिलेड टेस्ट में जगह मिल सकती है पर वह सलामी नहीं मध्यक्रम के बल्लेबाजी के तौर पर उतरेंगे। साथ ही कहा कि पिछले मैचों में ट्रैविस हेड और जेक वेदराल्ड का प्रदर्शन सलामी बल्लेबाज के तौर पर अच्छा रहा है, इसलिए वे दोनो ही पारी शुरु करेंगे। उन्होंने कहा कि नाथन लियोन को अंतिम ग्यारह में अवसर मिलना तय है। उन्हें दूसरे मैच में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी अब ठीक है और तीसरे मैच में खेलेंगे।

दूसरे टेस्ट में मैट हैनरी सहित तीन अनुभवी खिलाड़ियों के बिना ही उतरेगी न्यूजीलैंड

क्राइस्टचर्च ।न्यूजीलैंड को बुधवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरु हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच से पहले करारा झटका लगा है। न्यूजीलैंड टीम को इस मैच में मैच तीन अनुभवी खिलाड़ियों मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिचेल सेंटनर के बिना ही उतरना पड़ेगा।ये तीनों ही पहले टेस्ट में घायल हो गये थे और अभी तक नहीं उबरे हैं।ये तीनो ही स्टार खिलाड़ी तीसरे ओर अंतिम मैच में भी नहीं खेलेंगे। जिसकी वजह से वह कैरेबियन जायंट्स के खिलाफ दूसरे और तीसरे हेनरी और स्मिथ के चोटिल होने के बाद अनकैप्ड तेज गेंदबाज माइकल रे को न्यूजीलैंड ने शामिल किया है।वहीं क्रिस्टियन क्लार्क को अपनी टीम में जगह मिली है। रे ने वारविकशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेला है, जिसमें उन्होंने 30.28 की औसत से 14 विकेट लिए हैं।कुल मिलाकर दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 69 फर्स्ट-क्लास मैचों में 205 विकेट लिए हैं।30 साल के इस खिलाड़ी के नाम फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में आठ बार चार विकेट और तीन बार पांच विकेट हॉल हैं।वहीं फर्स्ट-क्लास में 24 साल के क्लार्क ने 27 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 33 की औसत से 77 विकेट लिए हैं।

इस सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था।

हीरो हॉकी महिला लीग इस माह के अंत में, पुरुष लीग अगले साल की शुरुआत में

रांची।हीरो हॉकी इंडिया के महिला लीग मुकाबले इसी माह 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक रांची में खेले जाएंगे जबकि पुरुष लीग 3 से 26 जनवरी तक चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी।हीरो हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा, पिछले सत्र की सफलता के बाद हमें इस बार और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।हमने पुरुष लीग को तीन शहरों में रखा है जिससे अधिक से अधिक प्रशंसक इस विश्वस्तरीय हॉकी का आनंद ले पायें।' वहीं हॉकी इंडिया लीग की गवर्निंग कमेटी के सदस्य भोला नाथ सिंह ने कहा, हीरो हॉकी इंडिया लीग में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का अवसर मिलेगा।ऐसे में आगामी सत्र अब तक का सबसे बेहतर सत्र होगा।इस कार्यक्रम के दौरान रांची रॉयल्स का आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया।ये लोगो टीम की जीवंत भावना और झारखंड की समृद्ध हॉकी विरासत के साथ मजबूत संबंध को दिखाता है।महिला लीग में कुल 13 मैच खेले जाएंगे। इसमें शामिल चार टीमों रांची रॉयल्स, एसजी पाइपर्स, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, और श्राची रारह बंगाल टाइगर्स के बीच डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में मुकाबले होंगे।वहीं अंक तालिका की शीर्ष दो टीमों के बीच 10 जनवरी को फाइनल होगा।इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन जैसे 10 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी।वहीं पुरुष लीग 3 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक चलेगी।पहला चरण चेन्नई में, दूसरा रांची में और तीसरा भुवनेश्वर में होगा।पुरुष लीग में आठ टीमें तमिलनाडु ड्रैगन्स, हैदराबाद तूफान, जीएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, श्राची रारह बंगाल टाइगर्स (वर्तमान चैंपियन), वेदांता कलिंग लांसर्स, रांची रॉयल्स, एसजी पाइपर्स और एचआईएल गवर्निंग काउंसिल हिस्सा लेंगी।पुरुष लीग में 33 मैच खेले जाएंगे, जिनमें अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे शीर्ष हॉकी राष्ट्रों के खिलाड़ी शामिल होंगे।सभी टीमें सिंगल राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे से खेलेंगी।शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी।क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर 23 जनवरी (भुवनेश्वर) को खेला जाएगा।वहीं दूसरा क्वालिफायर 25 जनवरी को खेला जाएगा।

श्रीलंका के खिलाफ टी20 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, 17 और 19 साल की युवा प्लेयर्स को मौका

नई दिल्ली । गुनालन कमालिनी और वैष्णवी शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर होने वाली पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मंगलवार को भारतीय महिला टीम में पहली बार शामिल किया गया।यह श्रृंखला 21 से 30 दिसंबर तक खेली जाएगी जिसके शुरुआती दो मैच विशाखापत्तनम में और बाकी तीन मैच तिरुवनंतपुरम में होंगे। 17 साल की विकेटकीपर बल्लेबाज कमालिनी ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई इंडियन्स के लिए नौ मैच खेले हैं लेकिन 19 साल की वैष्णवी को WPL नीलामी में शामिल नहीं किया गया था।कमालिनी और वैष्णवी को राधा यादव और उमा छेत्री के स्थान पर टीम में जगह दी गई है जो पिछले महीने एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। कमालिनी और वैष्णवी के अलावा टीम में सभी जाने-पहचाने नाम शामिल हैं।हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी कर रही हैं जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान हैं।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल से पहले चोटिल प्रतिका रावल की जगह टीम में जगह बनाने वाली आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा भी टीम का हिस्सा हैं।भारत और श्रीलंका नौ जनवरी को नवी मुंबई में डब्ल्यूपीएल 2026 शुरू होने से ठीक पहले पांच मैच की श्रृंखला खेलेंगे। इस द्विपक्षीय श्रृंखला का कार्यक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर में भारत में होने वाली सीमित ओवरों की श्रृंखला के पिछले महीने स्थगित होने के बाद घोषित किया गया था।भारत और श्रीलंका ने पिछली बार अक्टूबर 2024 में विश्व कप के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।

भारतीय टीम - हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष, जी कमालिनी, श्री चरणी और वैष्णवी शर्मा।

पहले दो नाम ये होने चाहिए, भारत की 2027 विश्व कप टीम पर बोले हरभजन सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 खेलने वाले सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली का समर्थन करते हुए कहा कि इन दोनों के लिस्ट में 'पहले दो नाम' होने चाहिए। रोहित और विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ब्लॉकबस्टर ODI सीरीज खेली। रोहित ने पहले और आखिरी ODI में दो शानदार हाफ-सेंचुरी लगाईं जबकि विराट ने रांची और रायपुर में लगातार दो शतक बनाए और इसके बाद विशाखापत्तनम में अर्धशतक लगाया।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए हरभजन ने कहा कि अगर कोई 'युवाओं के पीछे अनुभव खो देता है', तो यह बड़े मैचों में महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा, 'क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़े और बेहतर खिलाड़ी हैं? इसलिए आपको उन्हें साइडलाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उनके आस-पास टीम कैसे बनाई जाए। अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाने के चक्कर में अनुभव खो देते हैं, तो बड़े मैचों में समय-समय पर यह एक समस्या हो सकती है। इसलिए उन्हें खेलना चाहिए और यह एक बड़ा वर्ल्ड कप होगा क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि वे कभी दूसरा वर्ल्ड कप न खेलें।'

हरभजन ने कहा, 'जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ बैटिंग ऑर्डर जैसा दिख रहा है, वह इतना सॉलिड लग रहा है कि उन्हें खेलना चाहिए। वे अपनी फिटनेस बनाए रखेंगे। लेकिन यह सवाल कि वे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, युवा खिलाड़ियों की ओर देखना ठीक है, लेकिन उन खिलाड़ियों को नजरअंदाज़ न करें जो पहले से ही बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं।' पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, 'पिछले वर्ल्ड कप में भी वे फाइनल में चूक गए थे, क्योंकि पिच बहुत धीमी थी। अगर पिच तेज होती, तो इंडिया जीत जाता। बहुत प्रेशर था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बेहतर खेला और जीता। लेकिन रोहित शर्मा की लीडरशिप में भारत जिस तरह खेला, वह अविश्वसनीय था। इसलिए पहले दो नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली होने चाहिए और बाकी टीम उसके बाद बननी चाहिए।'

विराट ने सीरीज में 151.00 के एवरेज और 117 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 302 रन बनाकर टॉप रन-गेटर रहे जिसमें दो शतक और एक फिफ्टी शामिल थी। रोहित ने भी तीन इनिंग्स में 48.66 के औसत से 148 रन बनाए, जिसमें 110 से ज़्यादा का स्टाइक रेट और दो फिफ्टी शामिल थी। 'रो-को' इस साल ODI में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दो खिलाड़ी रहे। विराट ने 13 मैचों और इनिंग्स में 65.10 के औसत से 651 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और चार फिफ्टी शामिल हैं, उनका बेस्ट स्कोर 135 और स्ट्राइक रेट 96 से ज़्यादा रहा। दूसरी और रोहित ने 14 इनिंग्स में 50.00 के औसत और 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए, जिसमें दो शतक और चार फिफ्टी तथा 121* का बेस्ट स्कोर रहा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ऑस्ट्रेलिया : भीषण आग से दो राज्यों में 40 घरों तबाह, एक दमकल कर्मी की मौत

कैनबरा, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के दो राज्यों में लगी भीषण आग ने 40 घरों को तबाह कर दिया और एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण दमकल सेवा आयुक्त ट्रंट कर्टिन ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स के बुलाहडेह शहर के पास लगी आग को काबू में करते समय रविवार को 59 वर्षीय दमकल कर्मी की मौत हो गई। इस आग में 3,500 हेक्टेयर जंगल और चार घर नष्ट हो गए।

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबिआंतो आज से पाकिस्तान के दौरे पर

जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो सोमवार से पाकिस्तान की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा शुरू करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मामलों के कार्यालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है। सुबिआंतो पीएम शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आ रहे हैं। वह शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी व सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मिलेंगे।

पाकिस्तान : पानी और सफाई पर सिंध विधानसभा में हंगामा

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में परिवहन, पानी और सफाई पर तीखी बहस हुई, जहां विपक्ष ने कराची और हैदराबाद में बिगड़ते यातायात की आलोचना की, जबकि सरकार ने प्रमुख मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन विस्तार का वादा दोहराया। इस दौरान जनरल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने की बधाई देने पर राजनीतिक दल बंटे नजर आए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थित सदस्यों ने शर्म करो के नारे लगाए। हंगामे को देख स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह कादिर शाह ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी।

बांग्लादेश में छात्रों की पार्टी एनसीपी ने किया गठबंधन

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले छात्रों के नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी ने रविवार को जमात-ए-इस्लामी से अलग हुए दल अमर बांग्लादेश पार्टी और राष्ट्र संस्कार आंदोलन के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का नाम गणतांत्रिक संस्कार जोते रखा गया है।

ब्रिटेन : 171 डिलीवरी राइडर गिरफ्तार, कई भारतीय भी

लंदन, एजेंसी। ब्रिटिश सरकार ने बताया है कि ब्रिटेन भर में चलाए गए एक अभियान में 171 डिलीवरी राइडरों को अवैध रूप से काम करते हुए पकड़ा गया है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी को देश से निर्वासित करने के लिए हिरासत में लिया गया है। गृह ऑफिस की इमिग्रेशन एनफोर्समेंट टीमों ने पिछले महीने ऑपरेशन इक्वलाइज चलाया था। इसके तहत न्यूहैम (पूर्वी लंदन) और नॉर्विच समेत कई शहरों में छापे मारे गए।

नेपाल में एयरपोर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार पर चीनी कंपनी पर केस

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी (सीआईएए) ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर चीनी कंपनी सहित 55 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। एक विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज करते हुए सीआईएए ने चाइना सीएएमसी इंजीनियरिंग और 54 अन्य को आरोपी बनाया है। सीएमसी इंजीनियरिंग, चीनी कंपनी सिनोमैक के निर्माण प्रभाग की कंपनी है। आरोप है कि ठेकेदार और कंपनी ने गलत इरादे से काम किया।

छिड़ गई एक और जंग, थाईलैंड ने कंबोडिया पर कर दिया हवाई हमला; धरा रह गया ट्रंप का समझौता

बैंकॉक, एजेंसी। दुनियाभर में कई जगहों पर चल रहे युद्ध के संकट के बीच एशिया में एक जंग और छिड़ गई है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों में जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। थाईलैंड ने अमेरिकी की मध्यस्थता में चल रहे सीजफायर एग्रीमेंट की वार्ता भी रोक दी है। थाई सेना के मुताबिक कंबोडिया की तरफ से हुई गोलीबारी में उनका एक सैनिक मारा गाय था। इसके बाद इधर से भी जवाबी कार्रवाई की गई।

मेजर जनरल विंथाई सुवारी ने कहा कि चोंग अन मा पास के करीब कंबोडियाई सेना गोलीबारी करती है। वहीं कंबोडिया का कहना है कि थाईलैंड के सैनिकों ने पहले उकसावे की कार्रवाई की थी। थाईलैंड ने कहा है कि सीमा से सटे गांवों से करीब 70 फीसदी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। अक्टूबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए गए एक संघर्षविराम समझौते के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इससे पहले दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों ने जुलाई में पांच दिनों तक चले संघर्ष को जन्म दिया था, जिसमें कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचेता ने कहा कि थाई सेना ने ही सबसे पहले कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने सोमवार को शुरुआती हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा,

''कंबोडिया अनुरोध करता है कि थाईलैंड तुरंत सभी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोक दे, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं। अमेरिका द्वारा कराए गए संघर्षविराम पर पिछले महीने थाई सैनिकों के बारुदी सुरंग की चपेट में आने के बाद खतरा पैदा हो गया था। इसमें थाई सैनिक घायल हो गए थे। ट्रंप ने नवंबर के मध्य में कहा था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्ध को रोक दिया है जबकि तनाव अब भी बना हुआ है। युद्ध में उलझने वाले देशों के बारे लेकर लोगों की जिज्ञासा सबसे ज्यादा उनकी सेना को लेकर होती है। आखिर किसकी सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और वायुसेना में कितना दम है, तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है।

बजट और जमीनी सेना : रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कंबोडिया का रक्षा बजट करीब 1.3 अरब डॉलर था। उसके पास करीब 1.24 लाख सक्रिय सैनिक है। कंबोडिया की सेना की स्थापना 1993 में देश की पूर्व कम्युनिस्ट सेना और दो विद्रोही दलों से मिलकर बनी है। इसके अलावा इनके इनके पास करीब 200 सैन्य टैंक और 480 आर्टिलरी गन हैं। वहीं, दूसरी और थाईलैंड के ऊपर अमेरिका का हाथ रखा हुआ है। कंबोडिया के सामने इसका 5.7 अरब डॉलर का भारी भरकम सैन्य बजट हय् अमेरिका के नॉन नाटो सहयोगी के रूप में पहचान रखने वाले थाईलैंड की सेना में 3.60 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं। इनके पास 400 टैंक, 1200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 2600 आर्टिलरी हथियार हैं। इसके अलावा इनकी सेना के पास विमानन की भी एक अलग शाखा है।

वायुसेना में भी थाईलैंड ताकतवर : कंबोडिया की वायुसेना में 1500 सैन्य कर्मी शामिल हैं। इनके पास एक छोटा वायुसैनिक बेड़ा है। इसमें 10 ट्रांसपोर्ट जहाज और 10 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनके पास कोई फाइटर जेट नहीं है लेकिन 16 अन्य हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 6 सोवियत कालीन एमआई-17 और 10 चीनी जेड-9 विमान शामिल हैं। वहीं, दूसरी तरफ थाईलैंड की वायुसेना दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मजबूत वायुसेना मानी जाती है। इसके पास वायुसेना में करीब 46 हजार सैनिक हैं और 112 विमान युद्ध के लिए तैयार हैं। इनमें से 28 एफ-16, 11 स्वीडिश ग्रिपन जेट और दर्जनों हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

नौसेना भी थाईलैंड आगे : रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की नौसेना में करीब 2800 कर्मचारी हैं, जिनमें 1500 नौसैनिक इन्फ्रेंट्री शामिल हैं। इसके अलावा 13 गश्ती और तटीय पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट है। वहीं, दूसरी ओर थाईलैंड की नौसेना के पास जबरदस्त हथियार प्रणाली है। इसकी नौसेना में 70 हजार कर्मचारी हैं, जिनमें नौसैनिक विमानन, मरीन कोर और तटीय रक्षा और अनिवार्य सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्रिगेट, 68 गश्ती और तटीय युद्धपोत शामिल हैं। इसके अलावा इनकी नौसेना की अपनी एक अलग वायु शाखा भी है, जिसके पास कई विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं।

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैकड़ों साल से विवाद : थाईलैंड और कंबोडिया का इतिहास लंबे समय तक खमेर साम्राज्य (कंबोडिया) और सियाम साम्राज्य (थाईलैंड) के बीच टकरावों से जुड़ा रहा है। फ्रांस और ब्रिटिश शासन के दौरान भी दोनों देशों की सीमाओं को तनाव था।

ऑस्ट्रिया की बर्फीली चोटी पर ठंड में जमकर महिला की मौत, बॉयफ्रेंड पर लापरवाही का आरोप

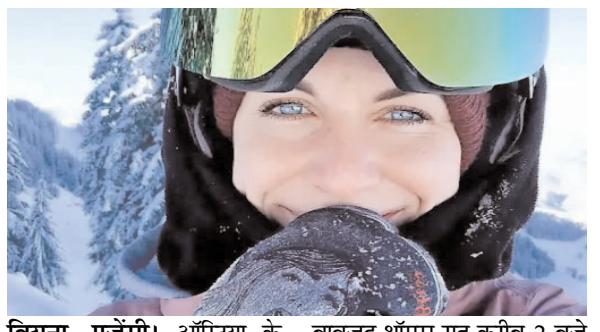

वियना, एजेंसी। ऑस्ट्रिया के सबसे ऊंचे पहाड़ ग्रॉसग्लॉकनर पर 33 साल की एक महिला कर्स्टिन गर्टनर की ठंड में जमकर मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, कर्स्टिन साल्जबर्ग की रहने वाली थीं और सोशल मीडिया पर खुद को 'विंटर चाइल्ड' और 'माउंटेन पर्सन' कहती थीं।

जनवरी में वह अपने बॉयफ्रेंड थॉमस प्लामबेर्गर के साथ चढ़ाई करने गई थीं। थॉमस 39 साल के हैं और एक अनुभवी माउंटेन गाइड हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने अपनी चढ़ाई दो घंटे देरी से शुरू की और ऊपर पहुंचते-पहुंचते मौसम बेहद खराब हो गया। तापमान -20डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और हवाएं तूफानी रफ्तार से चल रही थीं। चोटी से सिर्फ करीब 150 फीट नीचे कर्स्टिन बहुत थक गईं, उनका शरीर ठंड से सुन्न होने लगा और वह उलझन में दिख रही थीं।

सरकारी वकील का आरोप है कि इतनी खराब हालत में होने के बावजूद थॉमस रात करीब 2 बजे कर्स्टिन को वहीं छोड़कर मदद लेने निकल गए। उन्होंने न तो उनके ऊपर इमरजेंसी ब्लैंकेट डाला, न ही उनके पास मौजूद सेफ्टी कवर का इस्तेमाल किया।

यहां तक कि थॉमस ने तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल नहीं किया और फोन साइलेंट पर रख दिया, जिससे रेस्क्यू टीम की कॉल्स मिस हो गईं। पहाड़ की वेबकैम फुटेज में भी सिर्फ एक हेडलैंप दिखाई दिया, जो शिखर से दूर जाता हुआ दिखा। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू टीम सुबह वहां पहुंच सकी। तब तक कर्स्टिन की मौत हो चुकी थी। थॉमस पर अब ग्रॉस नेग्लिजेंस (गंभीर लापरवाही) से हुई हत्या का आरोप है, और दोषी पाए जाने पर उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है। उनके वकील का कहना है कि यह बस एक हादसा था। यह केस 19 फरवरी 2026 को इनसब्रुक रीजनल कोर्ट में सुना जाएगा।

इंसानों सी मानवीयता: मां के बाद बहन का सहारा बना ऑरंगउटान

जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशिया के गुनुंग पलुंा नेशनल पार्क के घने वर्षावनों में रहने वाले दो मादा ऑरंगउटानों रोसा और रॉनी को वैज्ञानिक लंबे समय तक मां-बेटी समझते रहे। दोनों साथ घूमतीं, एक ही घोंसले में सोतीं और बड़े प्यार से फल साझा करतीं। पर नेशनल ज्योग्राफिक में प्रकाशित नई स्टडी बताती है कि यह रिश्ता असल में मां-बेटी का नहीं, बल्कि बड़ी और छोटी बहन का था। बड़ी बहन रोसा ने मां की मौत के बाद छोटी रॉनी को गोद लेकर पाला। यह ऑरंगउटानों में गोद लेने का पहला विस्तृत वैज्ञानिक दस्तावेज है, जो इन एकाकी जीवों के सामाजिक व्यवहार की नई परतें खोलता है। दुनिया को पहली बार पता चला कि ऑरंगउटान परिवार के बच्चों को गोद देते हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी की मानवविज्ञानी चेरिल नॉट ने डीएनए विश्लेषण कराया तब जाकर दोनों बहनों का सच सामने आया।

दोनों की उम्र में रहा करीब सात

साल का फासला : सगी मां वेली थी, जो 2016 के बाद जंगल में नहीं दिखी। वेली की छोटी बेटी वाना को अंतिम बार 4 साल की उम्र में देखा गया था। बाद में पता चला कि वाना ही आगे चलकर रॉनी बनी। यानी मां की मौत के बाद बड़ी बहन रोसा ने उसे अपना लिया। 2017 में जब रोसा पहली बार रॉनी के साथ दिखी, वह लगभग 12 वर्ष की थी और रॉनी 5 वर्ष की।

चीन ने जापानी फाइटर जेट्स को निशाने पर लिया:दो बार फायर-रडार लॉक किया; बीजिंग का आरोपों से इनकार

टोक्यो, एजेंसी। जापान ने चीन पर उसके फाइटर जेट्स को निशाने पर लेने का आरोप लगाया है। जापानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक घटना शनिवार की है। आरोप है कि चीनी फाइटर जेट्स ने ओकिनावा द्वीप के पास इंटरनेशनल वॉटर्स में जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के विमानों पर दो बार फायर-कंट्रोल रडार लॉक किया। यह वह स्टेज है जब कोई फाइटर जेट अपने हथियारों वाला रडार सीधे टारगेट पर लॉक कर देता है। फायर-कंट्रोल रडार को मिसाइल दागने से ठीक पहले लॉक किया जाता है। जापान ने घटना पर चीन को कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पीएम साने ताकाइची ने इसे खतरनाक बताते हुए चीन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए कहा है। हालांकि चीन ने जापान के आरोपों से इनकार किया है।

चीन ने जापान को जिम्मेदार

ठहराया : चीनी सेना ने इस घटना के लिए जापान को जिम्मेदार ठहराया है। PLA ने कहा है कि जापानी विमानों ने चीनी ट्रेनिंग एरिया में बार-बार घुसपैठ की। इससे अभ्यास बाधित हुआ और उड़ान सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। घटना के वक्त चीनी कैरियर और तीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान जापान ने संभावित हवाई सीमा उल्लंघन को रोकने के लिए एफ-15 विमानों को तैनात किया था। जबाव में चीनी जे -15 फाइटर जेट्स ने लिआनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए एएसडीएफ के एफ-15 विमानों को रडार से निशाना बनाया। जापानी रक्षामंत्री शिंजिरो कोइजुमी के मुताबिक घटना में कोई विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।

ताइवान के मुद्दे पर चीन-जापान में तनाव बढ़ा : चीन और जापान के पिछले महीने ताइवान को लेकर जापानी पीएम साने ताकाइची के बयान के बाद तनाव बढ़ गया था। दरअसल ताकाइची ने 7 नंवबर को कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर-जिम्मेदार और उकसाने वाला बताया। इसके अगले ही दिन विवाद और बढ़ गया जब जापान में चीन के काउंसल जनरल शुए जियान ने एक्स पर लिखा कि वह इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने के लिए आगाह किया है और चेतावनी दी है।

ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन : चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि जापान और अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह मान्यता तो नहीं देते, लेकिन अमेरिका उसकी सुरक्षा में मदद करता है और उस पर किसी भी जबरन कब्जे का विरोध करता है। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है।

बांग्लादेश में चुनाव से पहले छात्र-नेतृत्व वाली नई पार्टी ने जमात से हाथ मिलाया

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में हाल में गठित छात्र नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी ने रविवार को जमात-ए-इस्लामी और एक अन्य समूह के साथ मिलकर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले 'गणतांत्रिक संगस्कार जोट' नामक गठबंधन बनाया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रोत्साहन से इस वर्ष फरवरी में गठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी), स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) का एक राजनीतिक संगठन है, जिसने पिछले साल हिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। प्रदर्शन के परिणामस्वरूप पांच अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर

होना पड़ा था। एनसीपी ने दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी की शाखा अमर बांग्लादेश (एबी) पार्टी और 'राष्ट्र संगस्कार आंदोलन' के साथ गठबंधन बनाया। एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे गठबंधन को 'गणतांत्रिक संगस्कार जोट' कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दो साल से अधिक के दीर्घकालिक प्रयासों का परिणाम है। इस्लाम सहित तीन छात्र नेता उस सलाहकार परिषद का हिस्सा थे जिसे यूनुस ने आठ अगस्त, 2024 को मुख्य सलाहकार का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद गठित किया था। हालांकि, इस्लाम ने एनसीपी के गठन के लिए अपना पद छोड़ दिया। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी, जमात-ए-इस्लामी ने फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए समान विचारधारा वाले राजनीतिक संगठनों के बीच एकजुटता बनाने के अपने प्रयासों के तहत हाल में आठ इस्लामी दलों का गठबंधन बनाया। यूनुस की सरकार ने हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया था। इस कारण से पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) देश के राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी बन गई थी। जिया वर्तमान में गंभीर रूप से बीमार हैं। जिया की बीएनपी का संचालन उनके बड़े बेटे और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान द्वारा किया जा रहा है, जो 2008 से लंदन में रह रहे हैं।

'आपको आईसीई के एजेंटों का आदेश न मानने का हक..', छापेमारी के बीच प्रवासियों से बोले जोहरान ममदानी

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क शहर के अगले मेयर जोहरान ममदानी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि प्रवासियों को अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) के एजेंटों से बात न करने या उनके आदेशों का पालन न करने का अधिकार है। यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है, जब आईसीई ने मैनहैटन में हाल ही छापेमारी की है।

वीडियो में ममदानी ने शहर के 30 लाख प्रवासियों की सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने कहा, 'अगर आप अपने अधिकार जानते हैं, तो आप आईसीई का सामना कर सकते हैं। ममदानी ने कहा कि अमेरिका में लोग संघीय आव्रजन एजेंटों से बात करने से इनकार कर सकते हैं। उन्हें बाधा पहुंचाए बिना उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें किसी निजी स्थान में प्रवेश करने से मना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईसीई एजेंट किसी जज के हस्ताक्षर वाले वारंट के बिना किसी घर, स्कूल या कार्यस्थल में प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा, आईसीई आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन आपको चुप रहने का अधिकार है। अगर आपको रोका जा रहा है, तो आप बार-बार पूछ सकते हैं- क्या मैं जा सकता हूं? जब तक वे जवाब न दें। ममदानी एक जनवरी को मेयर पद

की शपथ लेंगे। उनकी यह टिप्पणी उस घटना के एक सप्ताह बाद आई, जब प्रदर्शनकारी चाइनाटाउन के पास कैनाल स्ट्रीट पर उस समय एकत्र हो गए थे। आईसीई एजेंट लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे। पिछले अक्तूबर में भी इसी इलाके में ऐसी ही कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ था। ममदानी ने रविवार के वीडियो में कहा, न्यूयॉर्क हमेशा प्रवासियों का स्वागत करेगा और मैं हर दिन उनकी सुरक्षा, सहयोग और सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। कुछ हफ्ते पहले ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी व्हाइट हाउस में बैठक की थी। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में न्यू ऑरलियन्स सहित कई अमेरिकी शहरों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है।

जेलेंस्की ने पढ़ा तक नहीं यूएस का प्रस्ताव, ट्रंप कैसे रुकवा पाएंगे युद्ध; किस मूड में है रूस

कीव, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनके देश द्वारा तैयार किए गए उस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए 'तैयार नहीं हैं'। इसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है। दोनों मुल्कों के बीच फरवरी 2022 से ही सैन्य संघर्ष जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच मतभेदों को कम करने के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने तीन दिन की बातचीत पूरी की लेकिन रविवार रात पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने संकेत दिया कि वार्ता को आगे बढ़ने से रोकने वाले जेलेंस्की ही हैं। ट्रंप ने कहा, 'मुझे थोड़ी निराशा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा है, कुछ घंटे पहले तक यही स्थिति थी। उनकी टीम को यह पसंद है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं पढ़ा।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह पक्का नहीं कि जेलेंस्की को यह ठीक लगे। उनकी टीम को यह पसंद है लेकिन वह तैयार नहीं हैं।' रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' की योजना को सार्वजनिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। वास्तव में पिछले सप्ताह पुतिन ने कहा था कि ट्रंप के प्रस्ताव के कई पहलू अव्यावहारिक हैं। हालांकि, प्रस्ताव का मूल मसौदा मॉस्को के पक्ष में अधिक झुका हुआ था। जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने उन अमेरिकी अधिकारियों के साथ 'फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत' की है, जो फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्ता की प्रगति के बारे में फोन पर जानकारी दी गई। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'यूक्रेन अमेरिका के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वास्तविक शांति हासिल की जा सके।' ट्रंप ने

जेलेंस्की की आलोचना ऐसे वक्त में की है जब रविवार को रूस ने ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया। इसी बीच, अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता सोमवार को लंदन में जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। हमले जारी रूस द्वारा रविवार रात को किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से तीसरे दिन की वार्ता समाप्त हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र में शनिवार रात हुए ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई। इस बीच, केंद्रीय शहर क्रेमेन्चुक में बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन के संयुक्त हमले से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। यह शहर यूक्रेन की प्रमुख तेल रिफाइनरियों और औद्योगिक केंद्रों में से एक है। कीव और उसके पश्चिमी सहयोगियों का कहना है कि रूस लगातार चौथी बार सर्दियों में यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को निशाना बनाकर नागरिकों को गर्मी, रोशनी और पानी से वंचित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे 'ठंड को हथियार बनाना' बताया। हमलों के बीच, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने फ्लोरिडा में चल रही वार्ता में शामिल अमेरिकी अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा,'यूक्रेन अमेरिकी पक्ष के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने और शांति बहाल के लिए दृढ़ संकल्पित है।' यूक्रेन के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवर्तमान दूत कीथ केलॉग ने कहा कि वार्ता 'अंतिम चरण' में है और इसका समाधान भूभाग, मुख्य रूप से डोनबास, तथा जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र से जुड़े मुद्दों पर निर्भर करता है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वाराणसी में मानव तस्करी के दो दोषियों को उम्रकैद

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने बच्चे चुराकर राजस्थान और झारखंड में बेचने के मामले में दो युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला साक्ष्य, गवाहों और पुलिस चार्जशीट के आधार पर किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी कुलदीप पासवान (झारखंड, कोडरमा निवासी), नंदलाल राम (पश्चिम बंगाल, 24 परगना निवासी) को आजीवन कारावास और 15,000 का जुर्माना प्रत्येक पर लगाया है। 29 अप्रैल 2023 की रात दो बजे राजघाट निवासी पिंकी का एक साल का बच्चा घर से चोरी हो गया। इसके बाद 19 जुलाई 2023 को पुलिस ने कोडरमा से कमलेश पासवान को गिरफ्तार किया। कमलेश ने पूछताछ में बताया कि अनुराधा देवी (कोडरमा) ने उसके माध्यम से बच्चे को पश्चिम बंगाल के नंदलाल राम को बेचा। 20 जुलाई 2023 को पुलिस ने कुलदीप पासवान को लेकर नंदलाल राम के ठिकाने पर पहुंची, बच्चे को सकुशल बरामद किया और नंदलाल राम को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने गवाह, साक्ष्य और पुलिस चार्जशीट के आधार पर दोनों को दोषी पाया। बच्चे को अगवा करने वाली कार भी बरामद कर जब्त की गई थी। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण आठ अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। उसमें जगबीर बरनवाल, संतोष साव, अनुराधा देवी, गुड़िया, संगीता देवी, मनीष जैन, संतोष गुप्ता, शिखा देवी का नाम शामिल है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बच्चों की चोरी करके दलालों के माध्यम से राजस्थान, झारखंड और बिहार में निसंतान दंपती या जरूरतमंद लोगों को दो से पांच लाख रुपये में बेच देता था। इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

खजुराहो में रिसॉर्ट में खाना खाते ही बिगड़ी कर्मचारियों की तबीयत, 4 की मौत... बाकी का इलाज जारी

छतरपुर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में रिसॉर्ट में खाना खाने के बाद कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से गंभीर हालत में 9 कर्मचारियों को ग्वालियर रेफर किया गया। जहां 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। बाकी का इलाज हो रहा है। जानकारी के अनुसार, ग्वालियर जाने के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया। दो की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि, 5 का इलाज जारी है। इसमें दयाराम, हार्दिक, रवि, रोशनी और गोलू शामिल हैं। इसमें रवि, रोशनी और गोलू वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग के लक्षण बताए हैं। पहले जानकारी मिली थी कि 9 कर्मचारियों को छतरपुर जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल रेफर किया था। यहां तबीयत बिगड़ने पर 4 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां चारों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, तीन कर्मचारियों की मौत हुई है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने इनके परिजनों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्रशासन ने रिसॉर्ट सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि रिसॉर्ट मालिक विनोद कुमार गौतम बेल्जियम में रहते हैं। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट कर लिखा, जिस खजुराहो में कैबिनेट, उसी जिले में 4 मौत हो गईं, लेकिन सत्ता के महलों में बैठे मंत्री मौन हैं। 9 पीड़ित अस्पताल पहुंचाए गए, किंतु निर्लज्जता से भरी हुई निर्मम सरकारी कुर्सियां, उसी इलाके में सरकारी खर्चे पर मौज करती रहीं।

राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा के लिए कार्य स्थगित करने की मांग की

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में एक नोटिस पेश किया, जिसमें यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा के लिए कार्य स्थगित करने की मांग की। संसद का निचला सदन चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसमें कई राज्यों में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा शामिल होगी। विपक्षी दल महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एसआईआर के मुखर आलोचक रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल असली मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कर रही है। केसी वेणुगोपाल चुनाव सुधारों पर बहस में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। अन्य नेताओं में मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पदवी और एस ज्योतिमणि शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर पर चर्चा शुरू करने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। राहुल गांधी एसआईआर अभियान की लगातार आलोचना करते रहे हैं, उन्होंने मतदाता सूची में विसंगतियों और बीएलओ पर दबाव का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर एक सोची-समझी चाल है। जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव से बीएलओ की मौतों को सह-क्षति बताकर खारिज कर दिया है। यह कोई विफलता नहीं, बल्कि एक साज़िश है। सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए लोकतंत्र की बलि चढ़ा दी गई है।

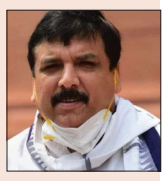

घटना के फौरन बाद फुकेत भाग गए नाइट क्लब के मालिक, आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा

पणजी (एजेंसी)। गोवा पुलिस ने कहा है कि नाइट क्लब के मालिकों का देश छोड़कर थाईलैंड भाग जाना, पुलिस जांच से बचने की उनकी मंशा को दिखाता है नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना तब हुई है, जिसमें दिल्ली स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा आग लगने की घटना शुरू होने के करीब छह घंटे बाद इंडिगो की उड़ान से फुकेत भाग गए थे। पुलिस उपाधीक्षक और जनसंपर्क अधिकारी नीलेश राणे ने बताया मुंबई स्थित आव्रजन ब्यूरो से संपर्क करने पर पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे, यानी घटना के तुरंत बाद, उड़ान (नई दिल्ली से फुकेत) में सवार हुए थे। इससे पुलिस जाँच से बचने की उनकी मंशा का पता चलता है। इंडिगो की उड़ान रद्द होने की खबर उस समय में आई है जब पूरे भारत में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, इस हफ्ते कई हवाई अड्डों पर हज़ारों उड़ानें रद्द कर दी गईं।

राज्यों में एसआईआर के काम में बाधा पर अदालत सख्त, कहा-चुनाव आयोग संज्ञान में लाए, हम आदेश पारित करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को धमकाने के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में कथित तौर पर बाधा डालने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की कमी को गंभीरता से लेने को कहा।

सर्वोच्च अदालत ने कहा, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पुलिस तो तैनात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास सभी सांविधानिक शक्तियां हैं, जिससे हम बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं से डील कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

इससे निपटें वरना इन हालातों से अराजकता हो सकती है।

पश्चिम बंगाल में पांच आईएएस नियुक्त

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कामकाज की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) नियुक्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उनमें रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार रवि कांत सिंह को प्रेसिडेंसी संभाग के लिए एसआरओ बनाया गया है, जबकि गृह मंत्रालय के नीरज कुमार बांसोद को मेदिनीपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कृष्ण कुमार निराला बर्दवान संभाग के लिए एसआरओ होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसआरओ की नियुक्ति से सभी संभागों में एसआईआर प्रक्रिया की जांच मजबूत होगी। राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर को शुरू हुआ था। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए मिला करीब तीन करोड़ रुपये का चंदा

हुमायूं कबीर के करीबियों ने बताया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद-शैली की मस्जिद के लिए मिले चंदे की राशि करीब तीन करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। विधायक के सहयोगियों ने बताया कि कबीर ने रेजीनगर में इस मस्जिद का शिलान्यास किया था।

कबीर के अनुसार, स्थल पर 12 दान पेटियां रखी गई थीं। अब तक इन पेटियों से 57 लाख रुपये की गिनती हुई है, जबकि क्यूआर कोड भुगतान के माध्यम से 2.47 करोड़ रुपये मिले हैं। योगदान के लिए शिलान्यास स्थल पर एक दान पेटी अब भी रखी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया था कि मस्जिद बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक करीब 1.3 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। कबीर के करीबी लोगों ने बताया कि चंदे के लिए जगह-जगह लगाए गए दानपत्र करीब भर चुके हैं और नकदी गिनने वाली मशीनों की मदद से रात भर चंदे की गिनती चलती रही। उन्होंने बताया कि लोग दान नकदी और ऑनलाइन दोनों तरीके से दे रहे हैं। कबीर के करीबी लोगों ने बताया कि चार दान पेटियों और एक बोरी से अब तक कम से कम 37.33 लाख रुपये नकद गिने गए हैं, जबकि क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन योगदान 93 लाख रुपये तक पहुंच गया है, जिससे कुल राशि 1.30 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि सात और सीलबंद पेटियों को खोला जाना बाकी है।

भारत घूमने आया चीनी शख्स, बिना अनुमति कश्मीर-लद्दाख के संवेदनशील क्षेत्रों में घूमता मिला

-पुलिस ने पकड़ा, मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा, जांच एजेंसियां अलर्ट

श्रीनगर (एजेंसी)। श्रीनगर में पकड़े गए एक चीनी नागरिक मामले ने सुरक्षा हलकों में हलचल मचा दी है। यह युवक पर्यटक वीज़ा पर भारत आया था, लेकिन जिस तरह वह बिना अनुमति संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्रों में घूमता रहा, उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब उसके मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं उसने कोई गोपनीय जानकारी तो साझा नहीं की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हू कॉन्गताई नाम का यह 29 साल का शख्स 19 नवंबर को दिल्ली आया था। उसके वीज़ा में केवल कुछ चुनिंदा बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति थी- जैसे वाराणसी, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर। इसके बावजूद वह लद्दाख के लेह, जांस्कर और कश्मीर घाटी के कई संवेदनशील इलाकों में घूमता रहा। जांस्कर में उसने तीन दिन बिताए और ऐसे स्थानों का दौरा किया जिन्हें रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। वह न केवल वहां घूमता रहा, बल्कि उसने किसी भी एफआरआरओ कार्यालय में पंजीकरण भी नहीं करवाया, जो विदेशी नागरिकों के लिए जरुरी है।

यह चीनी शख्स ट्रैवल रूट कई ऐसी जगहों से होकर गुज़रा, जहां आमतौर पर सुरक्षा कारणों से विदेशी पर्यटकों को रोक दिया जाता है। उसने दक्षिण कश्मीर के हावड़वान स्थित बौद्ध मठ और अवंतीपोरा के बौद्ध अवशेष देखे-जो सेना की विक्टर फ़ोर्स मुख्यालय के बेहद करीब हैं। इसके अलावा उसने हज़रतबल, शंकराचार्य हिल, डल झील और मुगल गार्डन जैसे स्थानों का भी दौरा किया।

भारत आने के तुरंत बाद उसने खुले बाजार से भारतीय सिम कार्ड भी हासिल किए, जो शक को और गहरा कर रहे हैं। उसके फोन में सीआरपीएफ तैनाती और अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जुड़े विषयों की ऑनलाइन खोजें मिली हैं। जांचकर्ता यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि क्या उसने कुछ ब्राउज़िंग डेटा हटाया है। पूछताछ में उसने बार-बार यह कहने की कोशिश की कि उसे वीज़ा नियमों की जानकारी नहीं थी। वह खुद को एक शौकिया यात्री बता रहा है और दावा करता है कि उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स पढ़ी है और पिछले नौ साल से अमेरिका में रह रहा था। उसके पासपोर्ट पर अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ब्राज़ील, फिजी और हांगकांग जैसे देशों की यात्रा मुहरें भी मिली हैं।

मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी का कहर बढ़ाया, राजस्थान में फिर से शीतलहर का दौर शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी का कहर बढ़ा दिया है। शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे जा सकता है।

राजस्थान के 19 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। फतेहपुर में सबसे कम, 4.4 डिग्री पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में 10 दिसंबर से शीतलहर चलने की आशंका जाहिर की है। दूसरी तरफ, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चमौली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में तेज बर्फबारी हुई। पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आए।

कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला

स्थित रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई। इसके कारण मनाली-लेह सड़क बंद कर दिया गई।

राजस्थान में फिर से शीतलहर का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 दिसंबर से शीतलहर का प्रभाव महसूस होगा। शेखावाटी और उसके आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर में 2 दिन का यलो अलर्ट है। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई है। यहां नदी, नाले और झरने भी जम गए हैं। केदारनाथ में तापमान माइनस 17 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में माइनस 14 डिग्री सेल्सियस चला गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई। खराब मौसम के कारण मनाली-लेह मार्ग को दारचा से आगे बंद कर दिया गया है।

अभिनेता विजय की रैली में बंदूक लेकर घुसा शख्स... रैली में मचा हड़कंप

-युवक-युवतियां और महिलाएं बैरिकेड फांदकर अंदर घुस गई

पुडुचेरी (एजेंसी)। तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय ने पुडुचेरी स्थित उप्पलम के एक्सपो ग्राउंड (न्यू पोर्ट) में विशाल रैली की। इस दौरान तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने बंदूक लेकर घुसने की कोशिश की, इससे रैली में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

व्यक्ति ने दावा किया कि उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। शख्स ने बताया कि वह एक निजी सुरक्षा अधिकारी है, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के कारण अपनी टीम के साथ नहीं जा पाया।

दूसरी तरफ अभिनेता विजय की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई। रैली में सिर्फ 5,000 लोगों की एंट्री की अनुमति दी गई थी। लेकिन, बड़ी संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंच गए। युवक-युवतियां और महिलाएं बैरिकेड फांदकर अंदर घुस गई। रैली में पहुंचे लोग विजय की झलक पाने के लिए पास के पेड़ों पर भी चढ़ गए।

भीड़ काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 27 सितंबर को करूर में टीवीके की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ के बाद विजय की यह पहली जनसभा थी।तमिलनाडु सरकार ने विजय को रैलियां निकालने की अनुमति देने से इंकार किया था।

विजय ने कहा कि केंद्र तमिलनाडु और पुडुचेरी को अलग-अलग मानती है, लेकिन हमारे लिए दोनों एक हैं। विजय ने कहा कि केंद्र ने पुडुचेरी के विकास में उसका साथ नहीं दिया है। पुडुचेरी विधानसभा ने सालों से राज्य का दर्जा देने की मांग वाले 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

ओवैसी ने बनाई दूरी अब हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन नहीं करेगी एआईएमआईएम

हैदराबाद (एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के साथ किसी भी चुनावी गठजोड़ से सोमवार को इनकार किया। साथ ही उनके प्रस्तावों को राजनीतिक रूप से संदिग्ध और वैचारिक रूप से असंगत बताया। एआईएमआईएम की ओर से यह बात ऐसे समय में कही गई है जब हुमायूं कबीर ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक समारोह में मस्जिद की नींव रखी थी।

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि कबीर को व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। वकार ने एक बयान में कहा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कबीर को अधिकारी के राजनीतिक तंत्र का हिस्सा माना जाता है। और यह सर्वविदित है कि अधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय स्तरीय नेतृत्व के मुख्य रणनीतिक ढांचे के भीतर काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय उकसावे से प्रेरित राजनीति का समर्थन नहीं करता। एआईएमआईएम नेता ने कहा, मुस्लिम समुदाय राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखता है, उसे तोड़ने में नहीं। वह देश को मजबूत करने वाली ताकतों के साथ खड़ा है और अशांति और विभाजन पैदा करने वालों को नकारता है।

पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का उल्लेख करते हुए वकार ने कहा, ओवैसी साहब की राजनीति संवैधानिक मूल्यों, शांति और सामाजिक सद्भाव पर आधारित है। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ सकते जिसके कार्य एकता को खतरे में डालते हों, सामाजिक मतभेदों को गहरा करते हों या विनाश की राजनीति को बढ़ावा देते हों। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान कबीर के हालिया कदमों के पीछे की राजनीतिक मजबूरियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। वकार ने कहा, लोग साफ तौर पर समझते हैं कि वह किसके इशारे पर, किस हद तक और किस मकसद से काम कर रहे हैं। कबीर को पिछले सप्ताह पार्टी नेतृत्व के साथ बार-बार टकराव के बाद टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने 22 दिसंबर को एक नया राजनीतिक दल बनाने की योजना की घोषणा की है।

आदित्य ठाकरे का दावा- एकनाथ शिंदे के 22 विधायक बदलेंगे पाला?

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन उथल पुथल की खबरें सुनाई देती हैं। हालांकि इसमें सच कितना है ये तो सियासतदार ही जाने पर जिस तरह के बयान आते हैं वो ठहरे हुए पानी में कंकर का काम कर ही देते हैं। शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि महायुति के एक सहयोगी दल के 22 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हो गए हैं और पाला बदलने को तैयार हैं। उनका परोक्ष तौर पर इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना की ओर था। हालांकि, सीएम ने इस दावे से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि शिंदे सेना सहयोगी दल है।

जून 2022 में, शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के विद्रोह के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में, जनवरी 2024 में,

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना है, जो भाजपा और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ राज्य में सत्तारूढ़ महायुति का एक घटक है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का नाम लिए बिना दावा किया, सत्ता पक्ष की एक पार्टी है और दो गुट हैं। एक गुट के 22 विधायक मुख्यमंत्री के करीबी हो गए हैं। उनके पास अच्छा धन है और वे मुख्यमंत्री के इशारों पर नाचने लगे हैं। उन्होंने विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि 22 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। वर्ली से विधायक ठाकरे ने कहा कि इन 22 विधायकों में से एक खुद को उप-कसान कहता है। उनका परोक्ष तौर पर इशारा उद्योग मंत्री उदय सामंत की ओर था। अतीत में, शिवसेना (यूबीटी) ने दावा किया था कि शिंदे और अजित पवार के साथ सामंत राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति को लेकर निष्क्रियता के मुद्दे पर, आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि सरकार विपक्ष के नेताओं से क्यों डरती है। फडणवीस ने कहा, अगर कोई ऐसा कहता है, तो कल कोई और दावा कर सकता है कि आदित्य ठाकरे के 20 विधायक भी भाजपा के साथ हैं। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। उन्होंने साफ किया है कि भाजपा को उनके विधायक लेने की कोई जरूरत नहीं है।

2026 में पांच राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव, कई क्षेत्रों में उपचुनाव की भी तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही देश एक नए चुनावी दौर में प्रवेश कर रहा है। आने वाले महीनों में देश के कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, क्योंकि वर्ष 2026 में पांच प्रमुख राज्यों- असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन राज्यों में चुनावी तैयारियां धीरे-धीरे गति पकड़ने लगी हैं और क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी रणनीतियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है।

असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जहां चुनाव आमतौर पर जातीय संतुलन, विकास कार्यों और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों पर केंद्रित रहते हैं। केरल की 140 सीटों वाली विधानसभा में वाम मोर्चा और कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देते हैं, जिससे यह राज्य देश की राजनीति में अलग पहचान रखता है। वहीं, दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु, जिसकी विधानसभा में 234 सीटें हैं, द्रविड़ राजनीति का गढ़ माना जाता है और यहां एआईएडीएमके तथा डीएमके के बीच मुख्य मुकाबला रहता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल 294 सीटों वाली विधानसभा के साथ राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले चुनावों में यहां तीखे राजनीतिक टकराव देखने को मिले थे, और 2026 में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की उम्मीद है। पुडुचेरी, जहां विधानसभा की 30 सीटें हैं, आकार में भले छोटा हो, लेकिन दक्षिण भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका अहम मानी जाती है।

यहां हो सकते हैं उपचुनाव

इसी बीच, देश के विभिन्न हिस्सों में कई विधानसभा सीटें विधायकों के निधन के कारण रिक्त हो गई हैं, जिन पर उपचुनाव कराए जाने हैं। गोवा की पोंडा सीट 15 अक्टूबर को भाजपा विधायक रवि नाइक के निधन के बाद खाली हुई। कर्नाटक की बागलकोट सीट कांग्रेस विधायक एच.वाई. मेती के 4 नवंबर को निधन के बाद उपचुनाव की प्रतीक्षा में है। महाराष्ट्र की राहुरी सीट भी भाजपा विधायक शिवाजी कर्दिले के 17 अक्टूबर को निधन के बाद रिक्त है। मणिपुर की ताडुबी सीट 18 जनवरी से खाली है, जहां पहले एनपीपी के एन. कायिसी विधायक थे। इसके अलावा नागालैंड की कोरिडांग सीट भी 11 नवंबर को भाजपा विधायक इमकोंग एल. इमचेन के निधन के बाद खाली हो चुकी है।

चुनाव आयोग इन उपचुनावों की तिथियों की घोषणा जल्द कर सकता है। इस प्रकार देश आने वाले नए साल के चंद महीनों में ही एक बार फिर व्यापक चुनावी सरगर्मी से गुजरने वाला है। ऐसे में इन चुनावों में जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता देखने को मिलेगी वहीं जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होगी।